RNI No. 58061/93 ▪ वर्ष - 21 ▪ अंक - 282 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- बेंगलूरु » बुधवार » 13-05-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 टी20 प्रारूप के मानसिक पहलू से निपटना जरूरी है : साल्वी
6 ऊर्जा संकट में सरकार बनी ढाल
7 उल्टे होकर शिल्पा शेट्टी ने बताए योग के फायदे

फर्स्ट टेक

रिजर्व बैंक ने मुंबई के सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को शहर स्थित सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी के कारण रद्द कर दिया। एक बयान में कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप, बैंक 12 मई, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक से बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने और एक परिसमापक नियुक्त करने के लिए कहा है। बैंक के बंद होने पर, प्रत्येक जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि पर पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

प्रधानमंत्री के आर्ट आफ लिविंग आश्रम जाने के मार्ग के पास से टाइमर और सर्किट बोर्ड मिला

बेंगलूरु/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस मार्ग से बेंगलूरु के बाहरी इलाके में स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम जाने वाले थे उसके पास से जिलेटिन मिलने की जांच कर रही पुलिस टीम को एक सर्किट और एक टाइमर भी मिला है। यह जानकारी पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को दी। राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने भी संकेत दिया कि इसी तरह की सामग्री मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की भी इस जांच में शामिल होने में रुचि है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम स्थल के पास सड़क किनारे से जिलेटिन की दो छड़ बरामद की गईं, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस ने यह पता लगाने के लिए शुरू की कि वह कहां से आयी और क्या उसकी मौजूदगी के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश थी।

रुपया 40 पैसे लुढ़ककर 95.68 प्रति डॉलर के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर

मुंबई/भाषा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ने से मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 40 पैसे औंधे लुढ़ककर 95.68 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि पश्चिम एशिया में 10 सप्ताह से जारी संघर्ष के गहराने और तेल एवं गैस आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंकाओं से बाजार की धारणा प्रभावित हुई है।

सूर्यास्त 13-05-2026 6:37 बजे | सूर्योदय 14-05-2026 5:54 बजे

BSE	NSE
74,559.24	23,379.55
(-1,456.04)	(-436.30)

सोना	चांदी
15,855 रु.	278,307 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद

नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द

सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी-2026' को प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर मंगलवार को रद्द कर दिया गया। सरकार द्वारा अनियमितताओं की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए जाने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की।

मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने कहा कि नई तिथियों की सूचना ''अगले सात से दस दिनों'' में दी जाएगी।

एनटीए ने तीन मई को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) आयोजित की थी।

परीक्षा रद्द होने से देशभर में मेडिकल अभ्यर्थियों में आक्रोश फैल गया। विद्यार्थियों ने एनटीए की क्षमता पर सवाल उठाए और मांग की कि परीक्षा एम्स-दिल्ली द्वारा आयोजित की जाए।

विपक्ष ने भी केंद्र सरकार पर प्रशासनिक विफलता, विद्यार्थियों के प्रति असंवेदनशीलता और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में बार-बार हुई चूक का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। उसने एनटीए में व्यापक सुधार की मांग भी की।

नासिक पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया

नासिक (महाराष्ट्र)/भाषा। नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने मामले में मंगलवार को एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। एक अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त किरणकुमार चौहान ने कहा, ''नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए आज सुबह राजस्थान पुलिस से अनुरोध प्राप्त हुआ। उसी के अनुसार, नासिक पुलिस की अपराध शाखा की द्वितीय इकाई ने एक व्यक्ति को पकड़ा है।''

नीट मामले पर राहुल का आरोप:

'तथाकथित अमृतकाल' अब 'विषकाल' बन गया है

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अनियमितताओं के आरोपों के चलते मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी-2026' को रद्द किए जाने के बाद मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का तथाकथित अमृतकाल अब 'विषकाल' बन गया है। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज़्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज़ लिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला- पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार।'' उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ़ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है।

सनातन धर्म विभाजनकारी है, इसे 'समाप्त' किया जाना चाहिए : उदयनिधि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को दावा किया कि सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है और उन्होंने इसे 'समाप्त' करने का आह्वान किया। उदयनिधि इससे पहले सितंबर 2023 में भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में द्रमुक नेता ने यह भी कहा कि विपक्ष, तमिल प्रार्थना गीत 'तमिल थाई वझ्थु'' को दरकिनार करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगा। उन्होंने सदन में अपने भाषण में कहा, ''सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है और उसे निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए।'' इससे पहले उदयनिधि ने 2023 में भी इसी तरह की टिप्पणी की थी जिससे एक बड़ा विवाद पैदा हो गया था। उन्हें हिंदू समर्थक संगठनों की आलोचना का शिकार होना पड़ा और उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज कराए गए थे।

उदयनिधि ने नई सरकार के हालिया शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में एक विशिष्ट शिकायत को उजागर करते हुए कहा कि राज्य के गीत को उसकी पारंपरिक प्राथमिकता के बजाय क्रम में तीसरे स्थान पर धकेल दिया गया।

भाजपा ने सनातन विरोधी टिप्पणी को लेकर उदयनिधि स्टालिन की आलोचना की

नई दिल्ली/चेन्नई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर किए गए नए हमलों की कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही पार्टी ने उन पर तथा अन्य विपक्षी दलों पर वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन के खिलाफ नफरत फैलाने में लिप्त होने का आरोप लगाया। भाजपा की प्रतिक्रिया उदयनिधि स्टालिन द्वारा मंगलवार को सनातन धर्म को समाप्त करने का आह्वान करने के बाद आयी है। स्टालिन ने दावा किया कि सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है। उन्होंने सितंबर 2023 में भी इस तरह की विवादास्पद टिप्पणी की थी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि ''तमिलनाडु में द्रमुक की चुनावी हार के बावजूद, उदयनिधि स्टालिन फिर वही करने लगे हैं जो वे सबसे अच्छा करते हैं – सनातन धर्म का अपमान और उसके खिलाफ नफरत फैलाना।''

सनातन शाश्वत है, उदयनिधि के चाहने से यह समाप्त नहीं होगा : होसबाले

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह (महासचिव) दत्तात्रेय होसबाले ने मंगलवार को द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन पर निशाना साधते हुए सनातन धर्म की तुलना वट वृक्ष से की और कहा कि उनके चाहने से यह समाप्त नहीं हो जायेगा।

होसबाले ने 'पीटीआई वीडियो' के साथ एक साक्षात्कार में कहा, ''सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है कि प्रकाश नहीं होना चाहिए या मुझे लगता है कि परछाईं नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि ये गायब हो जाएंगी।'' उन्होंने कहा, ''सनातन इस राष्ट्र की आत्मा और चेतना है। यह कोई धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक मूल्य और एक वैश्विक दृष्टि है।''

होसबाले से मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उदयनिधि के पहले भाषण के बारे में सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को समाप्त करने का आह्वान किया था।

उदयनिधि इससे पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं।

आरएसएस नेता ने कहा, ''यह उनकी राय है और लोगों ने चुनावों में इसका जवाब दिया है। लेकिन, केवल किसी के कह देने से ही सनातन समाप्त नहीं हो जायेगा।'' उन्होंने कहा, ''सनातन शाश्वत रूप से विद्यमान है। शाश्वतता ही सनातन है।

तमिलनाडु :

अबू धाबी जाने वाले विमान के पंख में आग लगने के बाद उड़ान हुई रद्द

चेन्नई/भाषा। अबू धाबी जाने वाले एक विमान के पंख में मंगलवार को आग लगने के बाद उसकी उड़ान रद्द कर दी गई। इस विमान में लगभग 280 यात्री सवार थे। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि विमानन कंपनी 'एतिहाद एयरवेज' का विमान उड़ान भरने की तैयारी में था तभी पायलटों ने आग देखी, जिसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतार लिया गया और किसी को कोई चोट नहीं आई। दमकल कर्मियों ने तुरंत आग बुझा दी और उड़ान रद्द कर दी गई। 'एतिहाद एयरवेज' की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो सका।□

शराब की 717 खुदरा बिक्री दुकानों को बंद करने का मुख्यमंत्री विजय ने दिया आदेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु में महिलाओं और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग के बीच मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय ने मंगलवार को राज्यभर में सरकारी स्वामित्व वाली 717 खुदरा शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया जिनमें पूजा स्थलों के पास स्थित 276 दुकानें भी शामिल हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विजय ने शराब की खुदरा दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। विपक्षी दल द्रमुक ने इस कदम को 'महज प्रचार' कहकर इसका मजाक उड़ाया। तमिलनाडु में शराब की बिक्री सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है।

विज्ञप्ति के अनुसार, इसके तहत अगले दो हफ्तों के भीतर पूजा स्थलों के पास स्थित 276 दुकानें, शैक्षणिक संस्थानों के पास स्थित 186 दुकानें और बस अड्डों के पास मौजूद 255 दुकानें बंद कर दी जाएंगी। राज्य में, विशेषकर महिलाओं और पीएमके जैसे कुछ राजनीतिक दलों की ओर से व्यापक मांग रही है कि तमिलनाडु में सभी शराब की दुकानें बंद कर शराबबंदी लागू की जाए। इसके जवाब में द्रमुक के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने दावा किया कि टीएएसएमएसी द्वारा संचालित दुकानें धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के बाहर मौजूद नहीं हैं।

उन्होंने मजाक उड़ाते हुए 'एक्स' पर कहा, क्या वे नई दुकानें खोलेंगे और फिर उन्हें बंद कर देंगे? यह महज़ प्रचार है। तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) राज्य भर में शराब की 4,765 खुदरा दुकानों का संचालन करता है। वर्ष 2025 में, तमिलनाडु में शराब की बिक्री से राजस्व 48,344 करोड़ रुपये था। टीएएसएमएसी विदेशों से आयातित शराब के 551 ब्रांड बेचता है, जिनमें लाइसेंस प्राप्त खुदरा दुकानों के माध्यम से बेची जाने वाली वाइन के 223 ब्रांड शामिल हैं।

असम के मुख्यमंत्री के रूप में

हिमंत ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की। इसी के साथ राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने लगातार तीसरी बार सत्ता की बागडोर संभाल ली।

हिमंत के साथ चार विधायकों ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इनमें भाजपा की अजंता नियोग और रामेश्वर तेली तथा राजग के सहयोगी दल असम गण परिषद (अगप) के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के चरण बोरो शामिल हैं। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा क्षेत्र में वेटरनरी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में हिमंत और चारों मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सरबानंद सोनोवाल और पबित्रा मार्गेरिटा, राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री तथा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद थे।

वैज्ञानिक प्रगति के वैश्विक विमर्श को 'संकीर्ण नजरिए' से देखा गया : जयशंकर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

संयुक्त राष्ट्र/भाषा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गणित के क्षेत्र में भारतीय सभ्यता के योगदान पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि दुनिया भर में वैज्ञानिक प्रगति को लंबे समय से 'संकीर्ण नजरिए' से देखा गया और उन ऐतिहासिक विकृतियों को 'सुधारने' की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में भारत के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का शीर्षक 'शून्य से अनंत तक – गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान' है। इसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) के सहयोग से आयोजित किया गया है।

जयशंकर ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपनी तरह की इस पहली ऐतिहासिक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा, जब हम संयुक्त राष्ट्र में एकत्रित होते हैं, तो अक्सर साझा विरासत की बात करते हैं। फिर भी यदि हम आधुनिक इतिहास के सफर को देखें, तो दुनिया भर में वैज्ञानिक प्रगति को वक्त और भूगोल की सीमाओं में बांधकर एक संकीर्ण नजरिए से देखा गया है।

उद्घाटन समारोह में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत बिनय प्रधान, प्रिंसटन विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर और फील्ड्स मेडल विजेता मंजुल भार्गव के साथ-साथ कई देशों के राजदूत और राजनयिक उपस्थित थे।

विदेश मंत्री ने कहा, जैसे-जैसे भू-राजनीतिक बदलावों से राजनीतिक और आर्थिक पुनर्संतुलन हो रहा है, यह अनिवार्य रूप से सांस्कृतिक पुनर्संतुलन का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। यह विविध विमर्शों के लिए जगह बनाकर किया जाएगा, जिसमें हमारे अतीत की अधिक व्यापक समझ शामिल है। जयशंकर दो से 10 मई तक जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पर थे।

सोमवार को अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान उन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो 'समहिता' (दक्षिण एशियाई पांडुलिपि इतिहास और पाठ्य संग्रह) परियोजना का हिस्सा है।

यह विशेष संवादात्मक प्रदर्शनी उन प्राचीन गणितीय अवधारणाओं पर प्रकाश डालती है जिनकी जड़ें भारत में हैं और जो आगे चलकर हजारों वर्षों में पूरी दुनिया में फैलीं, इनमें शून्य, दशमलव स्थान मान प्रणाली (डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम), बीजगणित और एल्गोरिदम से लेकर ग्रहों के मॉडल, खगोलीय गणना, क्रमचय-संचय (कॉम्बिनेटरिक्स), द्विआधारी गणना (बाइनरी एन्यूमरेशन) और रेखागणित का 'बौधायन-पायथागोरस प्रमेय' शामिल हैं।

प्रदर्शनी में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर से लेकर केरल के खगोल विज्ञान और गणित संप्रदाय तक के विद्वानों के योगदान को दर्शाया गया है।

जयशंकर ने कहा, ''हम जो यहां एकत्र हुए हैं, वे केवल दीवार पर लिखे अंकों को नहीं देख रहे हैं। हम उस सभ्यता का अवलोकन कर रहे हैं जिसका जन्म भारत की बौद्धिक मिट्टी में हुआ था। यह एक ऐसी विरासत है जिसका संबंध जितना अतीत से है, उतना ही भविष्य से भी है।''

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

दागी देश

कैसा चरित्र जन का होगा,
जनप्रतिनिधि यदि होंगे दागी।
गुण्डों की होगी मौज बड़ी,
सब भ्रष्ट बनेंगे सहभागी।
होगा समाज में विचलन तब,
सारे होंगे रोगी-रागी।
हर तरफ अराजकता होगी,
सड़कों पर घूमेंगे बागी।।

कांग्रेस नेतृत्व ने किया मंथन,

केरल के मुख्यमंत्री के नाम की आज हो सकती है घोषणा

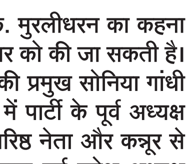

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम/भाषा। कांग्रेस आलकमान ने केरल के अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पार्टी की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्षों समेत कई नेताओं के साथ मंगलवार को मंथन किया और बुधवार को नाम की घोषणा की जा सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता के. मुरलीधरन का कहना है कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा बुधवार को की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के आवास '10 जनपथ' पर हुई बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और कन्नूर से लोकसभा सदस्य के. सुधाकरन के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एम.एम. हसन और के. मुरलीधरन तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तीनों कार्यकारी अध्यक्षों पी.सी. विष्णुनाथ, शफी परम्बिल और ए.पी. अनिल कुमार के साथ अलग-अलग मंथन किया।

'गबन' मामला

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के दो पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा सरकार की निधियों से 590 करोड़ रुपये के कथित गबन और कुछ अन्य संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा के दो पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32 शाखा के पूर्व प्रबंधक ऋषभ ऋषि और पूर्व संपर्क अधिकारी अभय कुमार को सोमवार को हिरासत में ले लिया गया।

वैश्विक चुनौतियां उद्योग जगत को सजग करने वाली, दक्ष और उत्पादक बनने की जरूरत : गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियां घरेलू उद्योगों को सजग करने वाली हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर और उत्पादक बनें, मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर उपयोग करें और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आयात पर निर्भरता कम करें। उन्होंने कहा कि दुनिया एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में युद्ध ने निश्चित रूप से वैश्विक व्यापार और निवेश प्रवाह को बाधित किया है, लेकिन इस 'कठिन समय' में भारत के पास दूसरों से आगे निकलने का एक बड़ा अवसर है।

मंत्री ने उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सालाना व्यापार सम्मेलन में कहा, ''प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) ने देशवासियों को एक स्पष्ट आह्वान किया है और अब सामूहिक कार्रवाई का समय है।'' गोयल ने कहा कि भारत ने लगातार संकट को अवसर में बदला है और प्रतिकूल परिस्थितियों में हमेशा मजबूत होकर उभरा है। उन्होंने कहा, ''वर्तमान वैश्विक स्थिति को भारत के लिए एक 'चेतावनी' के रूप में देखा जाना चाहिए ताकि वह अधिक कुशल, उत्पादक और आत्मनिर्भर बन सके।'' मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने का आह्वान किया क्योंकि इससे देश के तेल खर्च में भारी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे और परिवहन में सरकार का भारी निवेश और उद्योग के आयात खर्च को कम करने के लिए जारी प्रयास, चाहे वे किसी भी रूप में हों, देश को मजबूत बनाएंगे। ''मुझे चिंता करने का कोई कारण नहीं दिखता। मेरा मानना है कि हमें सशक्त होने की आवश्यकता है।'' उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प. एशिया संकट के मद्देनजर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, सोने की खरीद और विदेश यात्रा को स्थगित करने जैसे उपायों का आह्वान किया था।

उद्योग को आरएंडडी पर खर्च बढ़ाना होगा, संरक्षणवाद की प्रवृत्ति छोड़नी होगी: नीति आयोग सदस्य

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने मंगलवार को कहा कि सरकार सुधार जारी रखेगी और भरोसा-आधारित शासन के मूलभूत पहलुओं पर काम करेगी। हालांकि, उद्योग को अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर निवेश बढ़ाना होगा और संरक्षणवाद की प्रवृत्ति छोड़नी होगी ताकि भारत वैश्विक उत्पादन एवं नवाचार का आकर्षक केंद्र बन सके।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक व्यापार सम्मेलन में गौबा ने कहा कि सरकार सुधार एजेंडा को जारी रखेगी लेकिन उद्योग को कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना होगा जिसमें अनुसंधान एवं विकास में निवेश ''पहला'' मुद्दा है। उन्होंने कहा, '' जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का अनुसंधान एवं विकास पर कुल व्यय कम है। यह जीडीपी के लगभग 0.7% पर अटका हुआ है जो वैश्विक औसत 2.3% से काफी नीचे है। यह दक्षिण कोरिया तथा इजराइल जैसे देशों से बहुत कम है। इस 0.7% में से 60 प्रतिशत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।'' गौबा ने कहा, '' मेरा मानना है कि भारतीय उद्योग को अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश करना चाहिए एवं प्रौद्योगिकी आयात करने से उसे विकसित करने की ओर बढ़ना चाहिए। आरएंडडी में निवेश लागत नहीं है, यह रणनीतिक बढ़त है।'' उन्होंने भारतीय उद्योग से यह भी आग्रह किया कि वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती को स्वीकार करे, खासकर तब जब देश अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) कर रहा है।

नीति आयोग के सदस्य ने कहा, '' भारतीय उद्योग को संरक्षणवाद की अपनी प्रवृत्ति छोड़नी होगी। भारत सरकार ने ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के साथ महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए हैं और कई अन्य प्रक्रिया में हैं। ये भारतीय निर्यातकों के लिए नए बड़े बाजार खोलेंगे लेकिन मुक्त व्यापार का सिद्धांत पारस्परिकता की मांग करता है।'' गौबा ने इस बात पर जोर दिया कि उद्योग मानव संसाधन के कौशल विकास पर ध्यान दे क्योंकि सरकार अकेले यह नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, '' सरकार ने 'स्किल इंडिया मिशन' के माध्यम से महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। मेरा मानना है कि कौशल विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकता। उद्योग 4.0, कृत्रिम मेधा (एआई) और स्वचालन के उदय ने कार्यबल के कौशल विकास को अस्तित्व का प्रश्न बना दिया है।''

मोदी की अपील के समर्थन में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मुंबई में मेट्रो ट्रेन में यात्रा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई /भाषा। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई मितव्ययिता की अपील का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मंगलवार को यहां मेट्रो ट्रेन से यात्रा की और लोगों से ईंधन बचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की।

यहां बीकेसी और विधान भवन स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रेन की यात्रा करने के बाद आठवले ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का राजनीतिकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ये उपाय सुझाए हैं। उन्होंने कहा, ''मैंने व्यक्तिगत रूप से यह निर्णय लिया है कि पेट्रोल व डीजल की बचत करने के दृष्टिकोण से मेट्रो से यात्रा करना आवश्यक है। अन्य लोगों को भी मेट्रो से यात्रा करनी चाहिए और ईंधन बचाने में मदद करनी चाहिए।'' प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, सोने की खरीद और विदेश यात्रा को स्थगित करने समेत कई उपायों का आह्वान किया है।

मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते के चार शावक मृत पाए गए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्योपुर (मध्यप्रदेश)/भाषा। मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते के एक माह पहले जन्मे चार शावक मंगलवार सुबह मृत पाए गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया, ''आज सुबह करीब साढ़े छह बजे निगरानी दल को श्योपुर वन मंडल में मांद स्थल के पास चार शावक मृत मिले। मादा चीता 'केजीपी12' ने 11 अप्रैल को इन शावकों को जन्म दिया था। शव आंशिक रूप से खाए हुए पाए गए हैं।'' शावकों को आखिरी बार 11 मई की शाम जीवित देखा गया था। अधिकारी के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन शावकों की मौत किसी अन्य वन्यजीव के हमले के कारण हुई है। मादा चीता सुरक्षित और स्वस्थ है और शव परीक्षण व विस्तृत जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। इन चार शावकों की मौत के बाद भारत में अब कुल 53 चीते बचे हैं। अधिकारी ने बताया कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मे 33 चीतों समेत कुल 50 चीते हैं, जबकि राज्य के गांधी सागर अभयारण्य में तीन चीते मौजूद हैं। सभी जीवित चीते स्वस्थ हैं। इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से छह मादा और तीन नर समेत नौ चीते कूनो लाए गए थे। इससे पहले 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से आठ चीते भारत लाए गए थे, जबकि वर्ष 2023 में द. अफ्रीका से 12 चीते कूनो लाए गए थे।

क्या विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री विदेशी मुद्रा संबंधी चिंताओं से अवगत नहीं थे : ओवैसी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री के मितव्ययिता से जुड़े आह्वान पर आपत्ति जताते हुए सवाल किया कि नरेन्द्र मोदी और भाजपा ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान विदेशी मुद्रा बचाने की आवश्यकता पर चर्चा क्यों नहीं की?

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मितव्ययिता उपायों का आह्वान करने का एक उद्देश्य डॉलर बचाना है ताकि सरकार अमेरिका से तेल खरीदने के लिए 'ट्रंप को पैसे दे सके'। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान लोगों को यह बताए बिना वोट मांग रहे थे कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की कीमतें बढ़ाई जाएंगी? और अब वह इसे देशभक्ति के रूप में पेश करते हुए कह रहे हैं कि सच्चा देशभक्त वही है, जो इन सारी परेशानियों को सहन करे। उन्होंने दावा किया कि देश के लोगों को एक बिल मिलेगा जिसमें पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि होगी। उन्होंने पूछा कि क्या हाल में हुए राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड) ट्रंप कहते हैं कि ऊर्जा संकट से उबरने के लिए मुझसे खरीदारी करो, क्योंकि आपने व्यापार समझौता किया है।

'नीट प्रश्नपत्र लीक की 'साजिश' का पर्दाफाश करने को न्यायालय की निगरानी में जांच हो'

जम्मू/भाषा। कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई ने नीट-यूजी 2026 के कथित प्रश्नपत्र लीक मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में मंगलवार को जांच कराने की मांग की। पार्टी ने इसे 22 लाख से अधिक परीक्षार्थियों और उनके परिवारों को सीधे प्रभावित करने वाला एक ''बेहद गंभीर मसला'' करार दिया। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि शीर्ष अदालत बार-बार हो रहे प्रश्नपत्र लीक के पीछे के कथित नेटवर्क को उजागर करे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकाल में खूब सक्रिय हो रहा है।

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने आरोप लगाया कि बार-बार प्रश्नपत्र का लीक होना ''नोट छापने की मशीन और मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा घोटाला'' बन चुका है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किसानों से अनाज की शीघ्र खरीद के निर्देश दिए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को धान और अन्य फसलों की शीघ्र खरीद के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। उनकी ये टिप्पणी किसानों से अनाज की खरीद में कथित देरी को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में आई है।

रेड्डी ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में कहा कि किसानों से खरीद की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जमीनी स्तर पर दौरे करने को भी कहा गया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बोरियों की कमी से बचने के लिए कदम उठाने चाहिए और साथ ही अनाज की बोरियों को ट्रकों तक ले जाने वाले श्रमिकों की कमी को भी दूर करना चाहिए।

भीषण गर्मी और बेमौसम बारिश के कारण खरीद केंद्रों पर किसानों को हो रही कठिनाइयों के जवाब में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने हाल के हफ्तों में राज्य में खरीद में कथित देरी और किसानों की समस्याओं (जिनमें गर्मी, बेमौसम बारिश और नमी के नाम पर किसानों को परेशान करना शामिल है) के विरोध में प्रदर्शन किए हैं।

भक्त ने श्री वेंकटेश्वर प्राणदान ट्रस्ट को एक करोड़ रू से अधिक की राशि दान की

तिरुपति (आंध्र प्रदेश)/ भाषा। मुंबई के एक भक्त ने मंगलवार को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के श्री वेंकटेश्वर प्राणदान ट्रस्ट को एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि दान की। दान का डिमांड ड्राफ्ट तिरुमला स्थित अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी चि. वेंकैया चौधरी के शिविर कार्यालय को सौंपा गया। मंदिर प्रशासन की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई के विजय रमेश चंद्र ने टीटीडी श्री वेंकटेश्वर प्राणदान ट्रस्ट को 1.03 करोड़ रुपए दान किए। 2001 में स्थापित श्री वेंकटेश्वर प्राणदान ट्रस्ट का उद्देश्य हृदय, किडनी, मस्तिष्क, कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीब रोगियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। टीटीडी, तिरुपति स्थित दुनिया के सबसे समृद्ध हिंदू तीर्थस्थल माने जाने वाले श्री वेंकटेश्वर मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है।

सरकार को राहत देनी चाहिए, लोगों से समझौता करने को नहीं कहना चाहिए: कुमारी सैलजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने कहा कि लोग पहले से ही बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं और फिर भी केंद्र सरकार समाधान पेश करने के बजाय बार-बार उनसे त्याग और समझौता करने को कह रही है। सैलजा ने यहां जारी एक बयान में दावा किया कि इस तरह की बार-बार की अपीलें इस बात का संकेत देती हैं कि सरकार आर्थिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रही है।

सिरसा की सांसद सैलजा ने कहा कि कभी लोगों को पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी जाती है, तो कभी घरेलू खर्चों में कटौती करने को कहा जाता है। कभी-कभी उन्हें दैनिक आवश्यकताओं में भी कटौती करने को कहा जाता है। उन्होंने दावा किया, ये बार-बार की जाने वाली अपीलें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता की ये टिप्पणी ऐसे समय आयी है जब मोदी ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, सोने की खरीद और विदेश यात्रा को स्थगित करने जैसे उपायों का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव से लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। कुमारी सैलजा ने कहा कि नागरिकों को राहत प्रदान करना, स्थिर आर्थिक वातावरण बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

बाजार में भारी गिरावट से चार सत्रों में निवेशकों के 16.77 लाख करोड़ रुपए डूबे

नई दिल्ली/भाषा। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और लंबे समय तक भू-राजनीतिक संकट की आशंका के बीच बाजार में मची खलबली से पिछले चार कारोबारी सत्रों में निवेशकों की संपत्ति 16.77 लाख करोड़ रुपए घट गई।

इसके अलावा, विदेशी कोषों की निरंतर निकासी और रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने से निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं, जिससे वित्तीय बाजारों में बिकवाली बढ़ गई। मंगलवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,456.04 अंक या 1.92 प्रतिशत गिरकर 74,559.24 पर बंद हुआ।

पिछले चार कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 3,399.28 अंक या 4.36 प्रतिशत टूट चुका है। इन चार दिनों में बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 16.77 लाख करोड़ रुपए घटकर 4,56,02,981.70 करोड़ रुपए रह गया।

ऑनलाइन कारोबारी फर्म एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पोनमुडी आर ने कहा कि वैश्विक व्यापक आर्थिक परिदृश्य और घरेलू कारकों के दबाव ने निवेशकों की धारणा पर भारी असर डाला है। उन्होंने बताया, ''अमेरिका-ईरान वार्ता में गतिरोध, ऊर्जा कीमतों में उछाल, रुपए का रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरना और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार निकासी ने बिकवाली को तेज कर दिया है।'' वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड तीन प्रतिशत बढ़कर 107.4 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

अमरावती में भूमि साझा करने से इनकार करने वाले किसानों को अधिग्रहण नोटिस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अमरावती/भाषा। आंध्र प्रदेश के नगर पालिका प्रशासन मंत्री पी. नारायण ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती में भूमि साझा करने (लैंड पूलिंग) से इनकार करने वाले किसानों को भूमि अधिग्रहण के नोटिस जारी किए हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कदम केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही उठाया गया है।

लैंड पूलिंग के तहत लोग अपनी भूमि सरकार या एजेंसी को देते हैं तथा इसे विकसित कर इसका कुछ हिस्सा या अन्य भूमि उन्हें प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार अब भी ऐसे किसानों से स्वेच्छा से भूमि साझा करने के लिए आगे आने की अपील कर रही है। उन्होंने बताया कि कुछ किसान इसके लिए आगे आ रहे हैं,

जबकि कुछ अब भी इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

अमरावती दौरे के बाद जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में नारायण ने कहा, ''जहां किसान 'लैंड पूलिंग' के लिए आगे नहीं आए, वहां केवल मजबूरी में अधिग्रहण अधिसूचनाएं जारी की हैं।'' मंत्री ने यह भी बताया कि कुछ किसान इस मुद्दे पर अदालत का रुख कर चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही आगे बढ़ेगी।

नारायण ने आरोप लगाया कि युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) राजनीतिक मंशा से किसानों के मुद्दे पर बेवजह हंगामा खड़ा कर रही है। उन्होंने आगाह किया कि यदि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, तो जनता माफ नहीं करेगी। मंत्री ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि अमरावती के लिए 30,753 किसानों ने 35,017 एकड़ जमीन दी थी जिनमें से 30,079 किसानों को भूखंड आवंटित हो चुके हैं, यानी 97 प्रतिशत किसानों का आवंटन पूरा हो गया है।

उन्होंने कहा कि केवल 674 किसानों के 489 एकड़ से जुड़े आवंटन विभिन्न कारणों से लंबित हैं जिनमें 65 किसान न्यायालयी विवादों में उलझे हैं, 324 किसान आवंटन के पात्र ही नहीं हैं और शेष अन्य कारणों से लंबित हैं। नारायण ने बताया कि ग्रीनफील्ड राजधानी में 'ट्रंक रोड', 'लेआउट रोड' और अन्य निर्माण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ''अन्य राज्य भी अमरावती निर्माण की चर्चा कर रहे हैं।''

पंजाब सरकार अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति बनाएगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। पंजाब सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अपनी सेवा दे चुके अग्निवीरों को राज्य सरकार की नौकरियों में समायोजित करने के लिए आरक्षण नीति तैयार करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को यहां एक बैठक में इस नीति को सैद्धांतिक मंजूरी दी। उन्होंने इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति भी गठित की है, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जो इस नीति के ढांचे और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देंगे। इस समिति में वरिष्ठ अधिकारी विकास प्रताप, भावना गर्ग, सुमेर सिंह गुर्जर और एस.एस. श्रीवास्तव शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि आरक्षण नीति की रूपरेखा समयबद्ध और व्यापक तरीके से तैयार की जानी चाहिए, ताकि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों का प्रभावी पुनर्वास हो सके और उनकी क्षमताओं का उपयोग पंजाब के सामाजिक और आर्थिक विकास में किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों के आरक्षण और चयन से जुड़े मानदंडों को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, ताकि इन अत्यधिक प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं की सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को पुलिस, जेल विभाग, अग्निशमन सेवाओं, वन रक्षक, होम गार्ड और सरकार के अन्य विभागों में प्रभावी रूप से लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने हमेशा देश की एकता और अखंडता की रक्षा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, ''यह अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब न केवल देश का अन्न भंडार है, बल्कि इसे राष्ट्र की सशक्त भुजा के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब के लोग अपनी बहादुरी, सहनशीलता और उद्यमशीलता के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा में सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस और अग्निवीरों के जवानों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान के सम्मान में पंजाब सरकार पहले से ही शहीदों के परिवारों को एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यह कदम सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति पंजाब सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

तमिलनाडु के नये मंत्रिमंडल के आधे सदस्यों के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले : एडीआर रिपोर्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। तमिलनाडु में नवगठित मंत्रिमंडल के आधे मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 20 प्रतिशत मंत्रियों की संपत्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक है। एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।

एडीआर रिपोर्ट के अनुसार उसके विश्लेषण में सामने आया कि 10 मंत्रियों में से पांच (50 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है जबकि तीन (30 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित होने की सूचना दी है।

एडीआर का कहना है कि इन मंत्रियों में मात्र एक महिला है।

रिपोर्ट के मुताबिक दो (20 प्रतिशत) मंत्रियों की संपत्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक है, जिनमें मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय सबसे धनी हैं।

विजय की कुल संपत्ति 648.85 करोड़ रुपये है। मंत्रिमंडल की औसत संपत्ति 126.50 करोड़ रुपये है।

सबसे कम घोषित कुल संपत्ति वाली मंत्री कीर्तना एस हैं, जिनकी संपत्ति 22.57 लाख रुपये है। उन्होंने शिवकाशी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है।

रिपोर्ट के मुताबिक तीन मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता आठवीं से बारहवीं कक्षा के बीच बताई है, जबकि सात मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने स्नातक या उससे अधिक पढ़ाई की है।

एडीआर की एक पिछली रिपोर्ट में 233 विजयी उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया था।

उसमें कहा गया था कि 126 (54 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है, जबकि 56 (24 प्रतिशत) गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं।

कर्नाटक सरकार जिलेटिन की छड़ें बरामद होने संबंधी मामले की एनआईए जांच के लिए तैयार : परमेश्वर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार हाल में बेंगलूरु में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम स्थल के निकट जिलेटिन की छड़ें बरामद होने संबंधी मामले की जांच एनआईए को सौंपने के लिए तैयार है।

परमेश्वर ने कहा कि राज्य पुलिस ने प्रधानमंत्री के दौरे से काफी पहले जिलेटिन की छड़ों को ढूंढकर बेहतरीन काम'' किया और इस घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, मामले की जांच की जा रही है। मैं अभी और जानकारी साझा नहीं करना चाहता क्योंकि इस संबंध में जांच अभी जारी है। उस फोन कॉल के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 'आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन' के निकट बम लगाये जाने का दावा किया गया था। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल के निकट सड़क किनारे जिलेटिन की छड़ें बरामद कर ली हैं और इनकी जांच की जाएगी।''

उन्होंने कहा, ''मुझे सूचना मिली है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) इस घटना की जांच करना चाहता है। अगर वे मदद मांगेंगे तो हम करेंगे; उन्हें जांच करने दीजिए।'' परमेश्वर ने कहा कि ''उन कार्यक्रमों के लिए राज्य और केंद्र दोनों एजेंसियों द्वारा उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जाती है जिनमें प्रधानमंत्री को शामिल होना होता है। उन्होंने कहा कि जिलेटिन की छड़ें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दो घंटे पहले ही मिल गई थीं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उसने (पुलिस ने) अच्छा काम किया है।'' जब उनसे पूछा गया कि क्या इस घटना का आतंकवाद से कोई संबंध है, तो उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं पता। जांच पूरी होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच पूरी होने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं।''

शहर के बाहरी इलाके में, जहां से रविवार को प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरने वाला था, जिलेटिन की दो छड़ें मिली थीं, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंता पैदा हो गई थी।

मोदी कगलीपुरा के निकट कनकपुरा रोड पर स्थित आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन' केंद्र में आयोजित 45वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए बेंगलूरु में थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि एनआईए अधिकारियों की एक टीम ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जिलेटिन की छड़ें किसने रखी, इसकी पहचान करने और इसके मकसद का पता लगाने के लिए पुलिस रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। इस घटना की जांच के लिए चार निरीक्षकों समेत लगभग 50 कर्मियों वाली एक विशेष टीम का गठन किया गया है। कगलीपुरा पुलिस थाने में विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसी बीच, भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलु ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कथित तौर पर सुरक्षा संबंधी चूक की एनआईए से जांच की मांग की। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री जब भी दुनिया में कहीं यात्रा करते हैं, तो उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे में यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है कि जब वह राज्य में आए तो सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी?'' श्रीरामुलु ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले लगभग 100 निरीक्षकों का तबादला कर दिया गया था, और उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की आवश्यकता पर सवाल उठाया।

झोपड़ी में आग लगने से दो बच्चों की मौत हो गई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित कोथानूर में एक झोपड़ी में आग लगने से दो बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, सोमवार को दोनों भाई-बहन के खेलने के दौरान यह घटना हुई।पुलिस ने बताया कि मारे गए बच्चों में तीन साल की एक लड़की और पांच साल का एक लड़का शामिल हैं। उनके माता-पिता रायचूर जिले के दिहाड़ी मजदूर हैं और वे काम पर गए हुए थे। बच्चे हमेशा की तरह अपनी दादी के पास घर पर ही थे।

पुलिस ने बताया कि दादी शौचालय गई थी और उसी दौरान आग लग गई। पड़ोसियों तथा अन्य लोगों ने बच्चों को बचाने के प्रयास किए, जिसमें सफलता नहीं मिली। पुलिस ने बताया कि झुलसने और भारी धुएं के कारण बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। उसने बताया कि लड़के की मौके पर ही मौत हो गई जबकि लड़की ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जाएगी।

प्रदर्शन

कर्नाटक प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी के सदस्य मंगलवार को बेंगलूरु में कथित पेपर लीक के कारण नीट-यूजी परीक्षा रद्द होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए।

'ज्योतिषी' को मुख्यमंत्री का ओएसडी पद क्यों चाहिए : कांग्रेस सांसद सेंथिल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार द्वारा एक ''ज्योतिषी'' को विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) नियुक्त किए जाने पर मंगलवार को सवाल खड़े किये। पूर्व आईएएस अधिकारी सेंथिल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर उस पत्र की प्रति साझा की, जिसमें कथित तौर पर रिक्की राधन पंडित वेत्रिवेल को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त किए जाने की बात कही गई है। तिरुवल्लुवर लोकसभा क्षेत्र से सांसद सेंथिल ने लिखा, ''मेरी समझ से परे है। आखिर एक ज्योतिषी को ओएसडी पद की क्या जरूरत है? क्या कोई समझा सकता है?''

बारह मई को लिखा गया यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हालांकि, इस नियुक्ति की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए : उदयनिधि

चेन्नई/दक्षिण भारत । द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को दावा किया कि सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है और उन्होंने इसे 'समाप्त' करने का आह्वान किया। उदयनिधि इससे पहले सितंबर 2023 में भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन ने यह भी कहा कि विपक्ष, तमिल प्रार्थना गीत 'तमिल थाई वझ्झुथु'' को दरकिनार करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगा। उन्होंने सदन में अपने भाषण में कहा, ''सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है और उसे निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए।'' इससे पहले उदयनिधि ने 2023 में भी इसी तरह की टिप्पणी की थी, जिससे एक बड़ा विवाद पैदा हो गया था। उन्हें हिंदू समर्थक संगठनों की आलोचना का शिकार होना पड़ा था और उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज कराए गए थे। उदयनिधि ने नयी सरकार के हालिया शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में एक विशिष्ट शिकायत को उजागर करते हुए कहा कि राज्य के गीत को उसकी पारंपरिक प्राथमिकता के बजाय क्रम में तीसरे स्थान पर धकेल दिया गया। विपक्ष के नेता उदयनिधि ने कहा, ''...आपकी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुई ऐसी घटना एक गलती थी और आपको इस विधानसभा में इसे दोबारा होने नहीं देना चाहिए। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।''

उन्होंने कहा कि न केवल विधानसभा में, बल्कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम या तमिलनाडु में आयोजित किसी भी कार्यक्रम में, 'तमिल थाई वझ्झुथु' को हमेशा प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा, ''मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस पर कभी समझौता न हो। हमें अपने अधिकारों और परंपराओं की रक्षा के लिए बहुत सतर्क रहना होगा।'' उन्होंने दावा किया कि इस परंपरा से हटने से राज्य के लोगों में काफी आक्रोश है और उन्हें धक्का लगा है। उन्होंने सदन को 2023 की उस घटना की भी याद दिलाई, जब तत्कालीन द्रमुक सरकार ने राज्यपाल द्वारा प्रोटोकॉल में बदलाव करने के प्रयासों का विरोध किया था।

केपीएससी भ्रष्टाचार से ग्रस्त, युवाओं का भविष्य हो रहा बर्बाद : विजयेन्द्र येडीयुरप्पा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र येडीयुरप्पा ने राज्य की कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिस संस्था का काम योग्य उम्मीदवारों को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देना है, वही आज भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के कारण युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। विजयेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में 56,432 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, जो बेरोजगार युवाओं के बड़े आंदोलन के बाद लिया गया फैसला था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक इस भर्ती का कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। इससे लाखों युवाओं में असमंजस और नाराजगी है। उनका आरोप है कि केपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया चलानी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय इस पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार अदालतों ने भी आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और कुछ मामलों में दोषी अधिकारियों की पहचान भी हुई है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस सुधार नहीं किया गया है।

विजयेंद्र ने यह भी कहा कि अब आयोग नई तकनीक और सुधारों की बात कर रहा है, लेकिन युवाओं का भरोसा पहले ही टूट चुका है। उनके अनुसार, जब तक चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सख्त नियमों पर आधारित नहीं होगी, तब तक युवाओं का विश्वास वापस नहीं आ सकता। उन्होंने सरकार से मांग की कि बिना देरी के 56,432 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और प्रक्रिया को तेज और निष्पक्ष बनाया जाए। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बेरोजगार युवाओं का गुस्सा बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने ग्रुप ए, बी और सी के कई पदों को भरने के लिए भर्ती को मंजूरी दी है। कैबिनेट द्वारा 2026 की शुरुआत में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व विभागों में 400-पॉइंट रोस्टर प्रणाली और अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण का उपयोग करके पदों को भरना है।

वहीं दूसरी तरफ, राज्य में विपक्ष और कुछ विधायकों ने भी केपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में विधानसभा में इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई थी, जिसमें सुधार की मांग की गई थी। विपक्ष का कहना है कि जब लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर हो, तो सरकार को जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए।

केरल में मुख्यमंत्री के चयन के बाद कर्नाटक के नेतृत्व और कैबिनेट फेरबदल पर होगा फैसला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नेताओं को उम्मीद है कि केरल के मुख्यमंत्री का मुद्दा सुलझने के बाद पार्टी आलाकमान राज्य में नेतृत्व की कशमकश और बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल फेरबदल पर कोई फैसला करेगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने नौ अप्रैल को केरल विधानसभा का चुनाव जीता, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं किया है। वरिष्ठ नेता सतीश जारकीहोली और के एन राजन्ना ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर चल रही कशमकश को जल्द से जल्द दूर करने के लिए कांग्रेस आलाकमान से अनुरोध दिया। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस और राजनीतिक हलकों में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें जारी हैं।

पीडब्ल्यूडी मंत्री जारकीहोली ने यहां संवाददाताओं से कहा केरल के मुख्यमंत्री के चयन के बाद हमारा मामला (कांग्रेस आलाकमान के समक्ष) दूसरा है। केरल के मुख्यमंत्री का मामला सुलझने के बाद वे कर्नाटक पर ध्यान देंगे। अभी थोड़ा और इंतजार करते हैं। आलाकमान को पार्टी के भीतर मौजूद (नेतृत्व के मुद्दे पर) मतभेदों और विवादों को सुलझाना चाहिए। वे इसे कैसे सुलझाते हैं, यह आलाकमान पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल लंबे समय से चली आ रही मांग है और इसे सुलझाया जाना चाहिए।

जब जारकीहोली से पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि सिद्दरामय्या तभी जाएंगे जब आलाकमान उन्हें बुलाएगा और ऐसा केरल के मुख्यमंत्री का मामला सुलझने के बाद ही होने की संभावना है। उन्होंने कहा, पहले केरल के घटनाक्रम के शांत होने का इंतजार कीजिए, उसके बाद हमारी बारी है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि भ्रम की स्थिति को सुलझाया जाए और आलाकमान ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा।

जब उनसे पूछा गया कि आलाकमान के नेतृत्व में बदलाव करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि वे आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे। मैं भी यही कहूंगा। पूर्व मंत्री और विधायक राजन्ना ने यह भी कहा कि चूंकि केरल के मुख्यमंत्री का चुनाव अभी होना बाकी है, इसलिए उसके बाद कर्नाटक में जो भी घटनाक्रम या बदलाव होंगे, वह देखा जाएगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैंने पहले भी कहा था कि मई में कर्नाटक में राजनीतिक बदलाव होने की उम्मीद है। मई का महीना खत्म होने में अभी समय है। देखते हैं क्या होता है। राज्य में असमंजस की स्थिति है। अगर इसे सुलझाना है, तो सिद्दरामय्या को पद पर बने रहने और अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की अनुमति दी जानी चाहिए... मुझे उम्मीद है कि सिद्दरामय्या को अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की अनुमति दी जाएगी।

उन्होंने कहा, अगर आलाकमान नेतृत्व में बदलाव करना चाहता है, तो उन्हें फैसला लेने दें और ऐसा करने दें। कुछ न कुछ तो तय होना ही चाहिए, वरना इस भ्रम की स्थिति में प्रशासन ठीक से नहीं चल पाएगा। आलाकमान को जल्द से जल्द फैसला लेकर भ्रम की स्थिति को दूर करना होगा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका मतलब नेतृत्व में बदलाव का नहीं है, बल्कि इस बात पर जोर देना है कि कोई फैसला लेना जरूरी है।

शिवकुमार के समर्थक 2023 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या के साथ हुए कथित सत्ता-साझा करने के समझौते के अनुसार उनकी पदोन्नति पर जोर दे रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि शिवकुमार के जन्मदिन 15 मई तक खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस सरकार के पांच वर्षीय कार्यकाल का पचास प्रतिशत समय 20 नवंबर, 2025 को पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री पद में संभावित बदलाव की अटकलों के बीच सत्ताधारी पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर कशमकश जारी है।

प्रभाकर सर्वसम्मति से तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) विधायक जेसीडी प्रभाकर को मंगलवार को सर्वसम्मति से राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय ने उनके चुनाव के तुरंत बाद कहा कि विधानसभा की यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों की अपेक्षाओं को योजनाओं और कानूनों में परिवर्तित करें। तमिलनाडु विधानसभा के 17वें सत्र में अपने पहले भाषण में विजय ने कहा, ''यहां सभी समान हैं। विपक्षी सदस्यों और सत्ताधारी टीवीके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को समान महत्व दिया जाएगा। अच्छी बातों को स्वीकार किया जाएगा जबकि अवांछित विचारों को अस्वीकार किया जाएगा। इस विधानसभा को लोकतंत्र के दिल और दिमाग के रूप में कार्य करना चाहिए।''

विजय ने विधानसभा अध्यक्ष प्रभाकर और उपाध्यक्ष एम. रविशंकर को उनके संबंधित पदों पर निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए बधाई देने के साथ ही उन्हें सदन के सुचारू संचालन के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के एक उद्धरण से करते हुए इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा में सभी समान हैं। उन्होंने जनता, विशेषकर युवाओं के कल्याण और प्रशासन में पारदर्शिता के प्रति अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इसके अलावा, उन्होंने विधानसभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन किया जिसमें सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष नव निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष के हाथ पकड़कर उन्हें उनकी कुर्सी तक ले जाते हैं।

इससे पहले, कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष एम.वी. करुपैया ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रभाकर के नाम का प्रस्ताव रखा गया था और एकमात्र नामांकन प्राप्त होने पर उन्हें सर्वसम्मति से एवं निर्विरोध चुना गया है। करुपैया ने इस चुनाव के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के समाप्त होने की घोषणा की। उन्होंने सदन के नेता के. ए. सेंगोत्तैयान और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को सदन की परंपरा के अनुसार नव निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष को उनके आसन तक ले जाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि आज से प्रभाकर सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे।

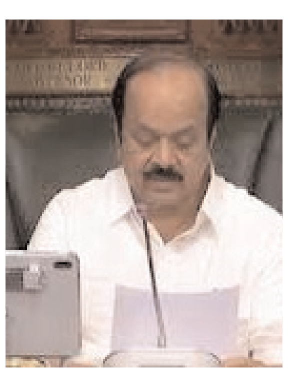

इसके बाद सेंगोत्तैयान और उदयनिधि ने प्रभाकर को बधाई दी। वे उन्हें सदन के मध्य स्थित उनके आसन तक ले गए जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आसन के दोनों ओर आमने-सामने बैठते हैं। पदभार ग्रहण करते ही प्रभाकर ने विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया। उन्होंने बताया कि थुरैयूर से टीवीके विधायक एम. रविशंकर उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र सदस्य हैं और उनका नामांकन सेंगोत्तैयान द्वारा प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई प्रतिद्वंदी न होने की वजह से रविशंकर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

उद्घाटन

केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता के साथ, मंगलवार को बेंगलूरु में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लॉन्च के दौरान दीप जलाते हुए।

राजस्थान सरकार ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को जानबूझकर छुपाने की कोशिश की : गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट यूजी 2026' में गड़बड़ी को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। साथ ही उन्होंने परीक्षा रद्द करने के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के फैसले को साहसिक बताया। उल्लेखनीय है कि एनटीए ने तीन मई को आयोजित 'नीट यूजी 2026' परीक्षा रद्द करने की घोषणा करते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने इसमें अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बयान में कहा, नीट (यूजी) प्रवेश परीक्षा का रद्द होना यह दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने जानबूझकर दो सप्ताह तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। गहलोत के अनुसार, एनटीए ने परीक्षा रद्द करके और सीबीआई को जांच सौंपकर युवाओं के हित में एक साहसिक निर्णय लिया है।

गहलोत ने इस मुद्दे को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राजस्थान की भाजपा सरकार ने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में हुए ओएमआर शीट घोटाले को छिपाया, ताकि सरकार की बदनामी न हो। कमजोर पैरवी के कारण उस मामले के आरोपियों को जमानत भी मिल गई। इसी प्रकार, अब नीट (यूजी) परीक्षा लीक की जानकारी को भी छिपाने का प्रयास किया गया और प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की गई।

पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार, अब सच्चाई सामने आ गई है और भाजपा सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। कांग्रेस नेता और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तथा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ने भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। जूली ने कहा कि नीट परीक्षा का रद्द होना इस बात का साफ सबूत है कि पूरे प्रकरण में संगठित तरीके से बड़ी धांधली हुई।

उन्होंने कहा, परीक्षा रद्द कर जांच सीबीआई को सौंपा जाना यह बताता है कि मामला कितना गंभीर और व्यापक है, यह लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खुला विश्वासघात हुआ है। उन्होंने कहा, भाजपा राज में 10 साल में 89 पेपर लीक, यही पेपर लीक की कड़वी सच्चाई है। हर बार बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, कार्रवाई के दावे होते हैं, लेकिन हकीकत में युवाओं की मेहनत, समय और भविष्य के साथ भाजपा सरकार लगातार खिलवाड़ कर रही है।

कांग्रेस नेता ने कहा, सबसे चिंताजनक बात यह है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने सच्चाई उजागर करने के बजाय उसे दबाने की कोशिश की और दो हफ्तों तक युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाए रखा। यह सरकार की केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सुनियोजित गैर-जिम्मेदारी और संवेदनहीनता का प्रमाण है।'

डोटासरा ने कहा, नीट 2026 परीक्षा रद्द होना सिर्फ एक परीक्षा का निरस्त होना नहीं है, ये मोदी सरकार लीक व्यवस्था एवं भाजपा सरकार और पेपर लीक माफियाओं की सांठगांठ का पर्दाफाश होना है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, राजस्थान में भाजपा के संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने लाखों युवाओं की मेहनत, वर्षों की तैयारी और सपनों को खुलेआम बाजार में बेच दिया जबकि सरकार तमाशा देखती रही।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मोदी सरकार एवं भाजपा शासित राज्यों में आज देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। एक के बाद एक पेपर लीक, भर्ती घोटाले और अब नीट जैसी परीक्षा का रद्द होना इस बात का सबूत है कि भाजपा राज में मेहनत नहीं, बल्कि पेपर लीक माफियाओं से सेटिंग और संरक्षण का खेल जारी है।

राजस्थान के अधिकतर इलाके भीषण गर्मी की चपेट में

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी का यह दौर इस हफ्ते जारी रहेगा तथा तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, मंगलवार सुबह तक बीते चौबीस घंटे में राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश कोटकासिम (अलवर) में 15.0 मिलीमीटर दर्ज की गयी। इस दौरान बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम केंद्र के अनुसार, राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन 'हीटवेव' व ऊष्णरात्री दर्ज होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण-पूर्वी भागों में भी आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच दर्ज होने व कहीं-कहीं 'हीटवेव' का अनुमान है। हालांकि राजधानी जयपुर तथा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर व भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं बादल छाये रहने, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने एवं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है।

शासन सचिव एवं संचार विभाग ने संपर्क हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। शासन सचिव, आयोजना, सांख्यिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विभागीय प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जन आधार में नाम जोड़ने, हटाने एवं शुद्धिकरण से संबंधित रिजेक्शन प्रकरणों का विस्तृत विश्लेषण कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम रूप में आमजन तक पहुंचाने पर विशेष बल दिया। साथ ही प्रदेश के सभी ई मित्रों को व्हाटसएप के माध्यम से नाम परिवर्तन प्रक्रिया की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए, जिससे अधिकाधिक आमजन को इसका लाभ मिल सके।

उन्होंने जिला-वार लंबित प्रकरणों के पृथक्करण (सेग्रीगेशन) तथा परिवादों के व्यवस्थित कारणों की जांच करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बैठक में मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित परिवेदनाओं का भी विश्लेषण किया गया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने परिवेदनाओं के सही श्रेणी निर्धारण एवं उचित मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। डॉ. सुरपुर ने कहा कि संपर्क पोर्टल के प्लेटफॉर्म पर अपनाई गई मूल कारण विश्लेषण (ठें उर्ीश -परश्रूळी) की कार्यप्रणाली समस्याओं के वास्तविक कारणों की पहचान कर उनके स्थायी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से केवल शिकायतों के तात्कालिक निस्तारण के बजाय उनके मूल कारणों का विश्लेषण कर दीर्घकालिक सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। इससे सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ-साथ आमजन का विश्वास भी सुदृढ़ हो रहा है।

सिजेरियन प्रसव के बाद महिलाओं की मौत का मामला : ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू में सख्त प्रोटोकॉल के निर्देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोटा। राजस्थान के कोटा में सिजेरियन (सी-सेक्शन) प्रसव के बाद संक्रमण के कारण चार महिलाओं की मौत के मद्देनजर राज्य की प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) गायत्री राठौर ने अस्पतालों के आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर (ओटी), गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों में उपचार प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। राठौर ने सोमवार रात यहां 'न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल' (एनएमसीएच) के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के आईसीयू का दौरा किया और वहां प्रसूताओं पिंकी, धन्नी बाई और आरती के परिजनों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।

उन्होंने आईसीयू में भर्ती रागिनी मीणा से भी बात की और बताया कि उनकी स्थिति में अब काफी सुधार है। एनएमसीएच और जेके लोन अस्पताल में दो-दो महिलाओं की सिजेरियन प्रसव के बाद उत्पन्न जटिलताओं के कारण मौत हो गई थी। सोमवार को दिहाड़ी मजदूर चंद्र प्रकाश की पत्नी पिंकी महावर (30) की सिजेरियन प्रसव के बाद संक्रमण के कारण मौत हो गई। 22 वर्षीय प्रिया महावर की 9 और 10 मई की दरमियानी रात को जेके लोन अस्पताल में सिजेरियन प्रसव के बाद गुर्दे में संक्रमण होने से मृत्यु हो गई।

इससे पहले पायल (26) और ज्योति नायक (19) की मृत्यु क्रमशः 5 और 7 मई को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गई थी। एक बयान के अनुसार, स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि मरीजों के उपचार की निगरानी वरिष्ठ गुर्दा रोग (नेफ्रोलॉजी) विशेषज्ञ डॉ. धनंजय अग्रवाल कर रहे हैं। डॉ. विकास खंडेलिया ने संक्रमण प्रभावित अन्य महिलाओं के इलाज के बारे में राठौर को जानकारी दी। राठौर ने नेफ्रोलॉजी वार्ड में स्थानांतरित की गईं चंद्रकला और सुशीला से भी मुलाकात की। उनके परिजनों ने बताया कि दोनों की स्थिति अब काफी बेहतर है। बाद में सोमवार को अधिकारी ने एनएमसीएच में एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ चिकित्सकों से उनकी राय जानी और संक्रमण से हुई मौतों के सभी संभावित कारणों पर विस्तृत चर्चा की।

वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ बैठक में राठौर ने निर्देश दिया कि जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी-सीएचसी) स्तर तक संक्रमण मुक्त ऑपरेशन थिएटर सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि चिकित्सा कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राठौर ने कहा कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने निर्देश दिया कि संक्रमण रोकने के लिए इन इकाइयों का नियमित विसंक्रमण (स्टरलाइजेशन) और उपकरणों की सफाई नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

राज्यपाल बागड़े ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल बागड़े ने विश्वविद्यालय परिसर में स्वास्थ्य केंद्र, विद्यार्थी और शोधार्थी बॉयज हॉस्टल एवं छात्रसंघ कार्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही निर्माणाधीन ऑडिटोरियम एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस अवसर पर विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। इनमें छात्र संघ भवन का निर्माण कार्य 2.42 करोड़ रुपए, औषधालय भवन 2.06 करोड़ रुपए, शोध छात्रावास (एक बिस्तर) 3.01 करोड़ रुपए तथा स्नातकोत्तर छात्रावास (दो बिस्तर) 3.03 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कार्य शामिल हैं।

राज्यपाल बागड़े ने राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक कर विश्वविद्यालय से संबंधित निर्माणाधीन विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों का निर्धारित शेड्यूल बनाकर नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जाए, ताकि सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे हो सकें।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शोध एवं नवाचार अपनाते हुए नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप में लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा के श्रेष्ठ मानदंड स्थापित करे। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का कार्य सितंबर माह तक पूर्ण किया जाए, जिससे विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के लिए अस्थायी डोम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े तथा विश्वविद्यालय को आर्थिक बचत हो सके।

टोंक जिलें के चैनपुरा में ग्राम रथ अभियान के तहत रात्रि चौपाल आयोजित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने टोंक जिले की मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चैनपुरा में ग्राम रथ अभियान के अंतर्गत रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं एवं सुझाव मंत्री के समक्ष रखे। मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राम रथ अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को उनका अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

रात्रि चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं से जलदाय मंत्री को अवगत कराया।

भीषण गर्मी के मद्देनज़र पीएचईडी मंत्री ने जनसुनवाई के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों को जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध जल कनेक्शनों पर विशेष निगरानी रखने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया, ताकि आमजन को निर्बाध एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उत्थान के लिए संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। चौधरी ने कहा हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का मजबूत इको-सिस्टम विकसित करने के लिए कार्य कर रही है और ग्राम-2026 का आयोजन उसी दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा किसान सम्मान निधि की राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया गया है।

जलदाय मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाते हुए प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 76 लाख से अधिक किसानों को 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं तथा बीमा पॉलिसी सृजित की गई है। उन्होंने कहा राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

ग्राम रथ अभियान के तहत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खेड़ापा में की जनसुनवाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित ग्राम रथ अभियान के अंतर्गत मंगलवार को शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) एवं पंचायती राज मंत्री तथा जिला जोधपुर प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने पंचायत समिति बावड़ी की ग्राम पंचायत खेड़ापा में आयोजित कार्यक्रम का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधा एवं आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं ।

विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है तथा ग्राम रथ अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रात्रि चौपाल एवं जनसुनवाई आयोजित की जाए, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को गांवों में जाकर आमजन से संवाद करना चाहिए ताकि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

ग्रामीणों द्वारा पेयजल संबंधी समस्याएं उठाए जाने पर प्रभारी मंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से मौके पर ही वार्ता कर वर्तमान स्थिति की जानकारी ली तथा समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है तथा यह आमजन का अधिकार है।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर।मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन हेतु विभागवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

मुख्य सचिव ने बैठक में निवेश परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत अवलोकन करते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि निवेशकों के लंबित प्रकरणों का निराकरण समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश का वातावरण सुगम, पारदर्शी एवं निवेशक-अनुकूल बनाए रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्य सचिव ने बैठक में निर्देश दिए कि भूमि रूपांतरण, पट्टा आवंटन, लेआउट अनुमोदन एवं एनओसी से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारित किया जाए।

साथ ही निवेशकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखा जाए एवं उन्हें उनके प्रकरणों की स्थिति से समय-समय पर अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि बहु-विभागीय समन्वय की आवश्यकता वाले प्रकरणों में संबंधित विभाग आपसी सहयोग से समाधान सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में हस्ताक्षरित एमओयू प्रदेश के आर्थिक विकास की आधारशिला हैं। इन परियोजनाओं के धरातल पर साकार होने से राजस्थान में रोजगार के अनगिनत नए अवसर सृजित होंगे, स्थानीय उद्योगों को गति मिलेगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

विकास को नई गति प्रदान करेगी 'डबल इंजन' असम सरकारः भाजपा अध्यक्ष नवीन

गुवाहाटी/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को कहा कि असम की 'डबल इंजन' सरकार विकास गतिविधियों, निवेश और जन कल्याण कार्यक्रमों में तेजी लाएगी। नितिन नवीन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और दूसरी बार पदभार संभालने पर शर्मा को बधाई दी। नवीन ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, ''यह अवसर असम के सुशासन, स्थिरता और विकास की दिशा में जारी यात्रा को नई गति प्रदान करने का प्रतीक है। 'डबल इंजन' राजग सरकार के रूप में, केंद्र और राज्य के बीच यह समन्वय मूलभूत अवसंरचना, निवेश, कनेक्टिविटी और जन कल्याण जैसे क्षेत्रों में नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा।'' भाजपा नेता डबल इंजन शब्द का प्रयोग पार्टी के केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में होने पर करते हैं।

'राजग का लगातार तीसरी बार सत्ता में आना असम के लिए एक महान दिन है'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमंत विश्व शर्मा को लगातार दूसरी बार असम का मुख्यमंत्री बनने पर मंगलवार को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का लगातार तीसरी बार सत्ता में आना ''असम के लिए एक महान दिन'' है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''असम के लिए एक शानदार दिन! लगातार तीसरी बार राजग सरकार ने सत्ता संभाली है। डॉ. हिमंत विश्व शर्मा जी को शपथ ग्रहण की हार्दिक बधाई!''

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ''शर्मा ने एक 'शानदार प्रशासक' के रूप में अपनी पहचान बनाई है और राज्य के लिए अग्रणी कार्य किए हैं। आगामी कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं!''

शर्मा ने पोस्ट का जवाब देते हुए कहा, '' जब हम नए जोश के साथ इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो इस अवसर पर उपस्थित होने और टीम असम को आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!''

उन्होंने कहा, ''पिछले एक दशक में असम के विकास को गति देने में आपकी दूरदृष्टि और नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आपके निरंतर सहयोग से हम इसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे।''

हिमंत मंत्रिमंडल में असम की सबसे लंबे समय तक विधायक रहने वाली महिला समेत चार नेता शामिल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। असम में मंगलवार को नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के साथ शपथ लेने वाले चार मंत्रियों में राज्य विधानसभा में सबसे ज्यादा समय तक सेवा देने वाली महिला विधायक, चाय बागान जनजाति के एक अनुभवी नेता और राजग में भाजपा के सहयोगी दल अगप तथा बीपीएफ के एक-एक वरिष्ठ नेता शामिल हैं।

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने असम में लगातार तीसरी बार सत्ता की कमान संभाल ली है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भाजपा नेता अजंता नियोग और रामेश्वर तेली के साथ-साथ असम गण परिषद (अगप) के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के चरण बोरो को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल हुए। हालांकि, नए मंत्रियों के विभागों की घोषणा अभी नहीं की गई है। तेली को छोड़कर बाकी तीनों मंत्री असम की पिछली राजग सरकार का भी हिस्सा थे।

अजंता नियोग : गोलाघाट से छह बार की विधायक नियोग 2001 से उक्त विस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनके नाम राज्य विधानसभा में सबसे लंबे तक सेवा देने वाली महिला विधायक होने का रिकॉर्ड दर्ज है। 2021 में वह राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री भी नियुक्त की गई थीं। नियोग (62) अतीत में कांग्रेस का हिस्सा रह चुकी हैं।

रामेश्वर तेली : चाय बागान जनजाति के प्रमुख नेता तेली केंद्र की मोदी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति की दुनिया में सक्रिय तेली ने 2001 में दुलियाजान निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर राज्य विधानसभा में पहली बार दस्तक दी। 2006 के चुनाव में भी वह इस सीट को बरकरार रखने में कामयाब रहे।

अतुल बोरा : अगप अध्यक्ष बोरा 2014 से इस क्षेत्रीय पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। वह 'ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन' के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन नेताओं में शामिल हैं, जो 1979-85 के विदेशी विरोधी असम आंदोलन के दौरान उभरे थे। पांच बार के विधायक बोरा (66) ने 1996 में गोलाघाट में जीत के साथ राज्य विधानसभा में पहली बार कदम रखा था। 2016 में उन्होंने बोकाखाट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वह लगातार तीसरी बार इस सीट से विधायक चुने गए हैं। बोरा ने पिछली राजग सरकारों में कृषि, सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास और असम समझौते का कार्यान्वयन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की कमान संभाली थी।

चरण बोरो : बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के माजबत से तीसरी बार विधायक चुने गए चरण बोरो (46) नए मंत्रिमंडल में शामिल निचले असम से एकमात्र मंत्री हैं। वह अक्टूबर 2025 में राजग के पिछले मंत्रिमंडल के आखिरी विस्तार के दौरान उसमें शामिल हुए थे, जब उनकी पार्टी बीटीआर परिषद चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद भाजपा नीत गठबंधन का हिस्सा बन गई थी। पिछली सरकार में चरण बोरो ने परिवहन मंत्री के रूप में सेवा दी थी और कई अन्य जिम्मेदारियां भी संभाली थीं।

राजग शासन ने असम को 'हिंसा के केंद्र' से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के केंद्र में बदल दिया : शाह

गुवाहाटी/भाषा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 10 वर्षों में असम हिंसा के केंद्र से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विकास के केंद्र में बदल गया है। यहां मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेते हुए शाह ने कहा कि लोग भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को उसकी उपलब्धियों के शानदार रिकॉर्ड के कारण बार-बार चुनते हैं। शाह ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, पिछले 10 वर्षों में, असम हिंसा के केंद्र से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विकास के केंद्र में बदल गया है। पूर्वोत्तर राज्य कई दशकों तक उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा। उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने विकास और सुरक्षा की एक मजबूत नींव रखी है, जिस पर अब प्रगति की एक भव्य इमारत खड़ी की जाएगी।

असम की हिमंत सरकार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगी : राजनाथ

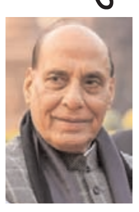

गुवाहाटी/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम में बनी राजग सरकार विकास, समावेशी विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगी।

यहां शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सिंह ने शर्मा के आगामी कार्यकाल के सफल और प्रभावशाली रहने की कामना की।

सिंह ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और उनके कुशल नेतृत्व में असम विकास, समावेशी विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा।''

शर्मा ने सिंह द्वारा दी गई शुभकामनाओं के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार एक बेहतर और उज्ज्वल असम के निर्माण की दिशा में काम करना जारी रखेगी।

लोगों की शिकायतों पर हो तुरंत कार्रवाई, लापरवाह अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे : विजय चौधरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार में जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भरोसा दिलाया है कि सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी तरह गंभीर है।

एक दिन पहले सरकार द्वारा 'सहयोग' पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 शुरू किए जाने के बाद मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि लोगों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं और यह व्यवस्था लगातार जारी रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी तरह गंभीर है। जदयू कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और मंत्री शीला कुमारी मंडल ने लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान चौधरी ने कहा कि सरकार पहले से जनसुनवाई कार्यक्रम चलाती रही है और अब इसे और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रतिदिन जदयू कार्यालय में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जहां आम लोग सीधे अपनी समस्याएं रख सकेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शुरू किए गए 'सहयोग' पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से लोग घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा में समाधान नहीं हुआ तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अथवा स्वत: निलंबन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हेल्पलाइन सेवा सुबह आठ से रात आठ बजे तक संचालित होगी। जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोना कम खरीदने और तेल बचाने की अपील का भी समर्थन किया।

'क्या गारंटी है कि दोबारा होने वाली नीट की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक नहीं होगा'

लखनऊ/भाषा। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) परीक्षा रद्द होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि पेपर लीक की बार-बार हो रही घटनाओं से लाखों छात्र और उनके परिजन नाराज हैं। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में दोबारा होने वाली परीक्षा की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, क्या गारंटी है कि परीक्षा दोबारा करवाने पर प्रश्नपत्र लीक नहीं होगा। इस समाचार से लाखों बच्चों और परिजनों के बीच भाजपा की भ्रष्टाचारी व्यवस्था के विरुद्ध बेहद आक्रोश और हताशा है। सपा प्रमुख ने पोस्ट में कहा, जब तक भाजपा सरकार रहेगी, परीक्षा होती रहेगी लीक, भाजपा के जाने के बाद ही परीक्षा प्रणाली होगी ठीक।

प. बंगाल के खेल मंत्री ने 'मेस्सी प्रकरण' की जांच के संकेत दिए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी से जुड़े विवादित प्रकरण की जांच के मंगलवार को संकेत दिए और आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण राज्य में खेल व्यवस्था प्रभावित हुई।

खेल विभाग का कार्यभार संभालने के बाद प्रामाणिक ने कहा कि उन्होंने इस घटना से संबंधित फाइल मंगवाई है, जिससे संकेत मिलते हैं कि आयोजन से जुड़े अधिकारियों और आयोजकों की भूमिका की संभावित जांच की जा सकती है। मेस्सी विवाद पिछले वर्ष दिसंबर में सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से जुड़ा है, जहां महंगे दामों पर टिकट खरीदने के बावजूद हजारों दर्शक अत्यधिक भीड़भाड़, कथित राजनीतिक हस्तक्षेप और सुरक्षा में चूक के कारण मेस्सी को नहीं देख पाए थे। बाद में दर्शकों के एक वर्ग ने स्टेडियम के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ भी की थी। तत्कालीन खेल मंत्री अरूप विश्वास उस समय आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे, जब कुछ वीडियो में उन्हें और अन्य विशिष्ट लोगों को मैदान पर मेस्सी के अगल-बगल देखा गया। इसके बाद आरोप लगे कि राजनीतिक हस्तक्षेप ने पूरे आयोजन को बाधित कर दिया। प्रामाणिक ने कहा, यह बेहद दुखद घटना थी। मैंने फाइल मंगवाई है और जरूरत पड़ने पर मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। हमारी कोशिश मेस्सी प्रकरण से प्रभावित लोगों की पीड़ा कम करने की होगी।''

आईआईटी-भुवनेश्वर ने कामकाजी पेशेवरों के लिए साइबर सुरक्षा में एमटेक शुरू किया

भुवनेश्वर/भाषा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भुवनेश्वर ने विभिन्न उद्योगों में कार्यरत इंजीनियर के लिए साइबर सुरक्षा में उद्योग-संबंधित एमटेक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। संस्थान ने एक बयान में कहा कि यह कार्यक्रम 24 जुलाई से शुरू होने वाला है और वर्तमान में उन योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन खुले हैं जो इस नए व लचीले शिक्षण मॉडल के माध्यम से साइबर सुरक्षा में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि यह पाठ्यक्रम भारत की अग्रणी साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और 'सिमुलेशन' कंपनियों में से एक 'व्हिजहैक टेक्नोलॉजीज' के साथ रणनीतिक सहयोग से विकसित किया गया था और इसे विशेष रूप से कामकाजी पेशेवरों के लिए बनाया गया है।

झारखंड में जल और बिजली किल्लत को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रांची/भाषा। झारखंड में कथित जल और बिजली किल्लत के विरोध में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मंगलवार को पूरे राज्य में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया।

रांची में राज्य की भाजपा इकाई के अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जल संकट के प्रतीक के रूप में घड़े लेकर जिला स्कूल ग्राउंड से कलेक्ट्रेट तक मार्च किया।

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जल और बिजली की निर्बाध आपूर्ति की मांग करते हुए नारे लगाए।

सेठ ने राज्य सरकार पर लोगों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि पूरे राज्य में लोगों को पीने के पानी की गंभीर कमी और लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने दावा किया, सरकार राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त है और बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें भी मुहैया कराने में नाकाम रही है। रांची के निवासियों को आठ से दस घंटे की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी बदतर है।

साहू ने कहा कि भाजपा पिछले एक सप्ताह से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है और आगाह किया कि अगर सरकार स्थिति में सुधार करने में विफल रही तो प्रदर्शन और तेज हो जाएगा।

झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलीं

रांची/भाषा। झारखंड के कुछ हिस्सों में मंगलवार दोपहर को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने से कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य में 18 मई तक बारिश, गरज के साथ बूंदाबांदी और दिन के तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है।

अधिकारी ने बताया कि रांची में कांके, मोराबादी, ईस्ट जेल रोड, लाइन टैंक रोड और क्लब रोड पर पेड़ उखड़ गए, जिससे सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। उन्होंने बताया कि ईस्ट जेल रोड पर एक बड़ा पेड़ कार पर गिर गया जिसमें कार चला रहा एक व्यक्ति बाल-बाल बच गया और इसी तरह की घटनाएं लाइन टैंक रोड और कुछ अन्य स्थानों से भी सामने आई हैं। अधिकारी ने बताया कि तेज हवाओं के कारण बिजली के कई खंभे क्षतिग्रस्त हो जाने से शहर में बिजली भी गुल हो गई। रांची मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, झारखंड के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में 14 मई तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसमें कहा गया है, 15 मई को सुबह 8:30 बजे से 16 मई को सुबह 8:30 बजे तक झारखंड के 12 जिलों के लिए आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट (तैयार रहें) जारी किया गया है। खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

ओडिशा : धान नहीं बेच पाने से परेशान किसान ने इच्छा मृत्यु की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा में बरगढ़ जिले के एक किसान ने सरकारी मंडी में अपना धान नहीं बेच पाने के कारण सरकार से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। भेदेन प्रखंड के सहारा टिकरा गांव के रोहित भोई नामक किसान ने सोमवार को बरगढ़ के जिलाधिकारी आदित्य गोयन को एक याचिका सौंपी। गोयन जन शिकायत सत्र के लिए आए थे।

किसान भोई ने याचिका में लिखा, छह महीने तक खरीद का इंतजार करने के बाद भी धान नहीं बिक पाने के कारण मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूं। मैं बहुत परेशान हूं और अपने बुजुर्ग माता-पिता के लिए दवा और बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ हूं। इसलिए मर जाना ही बेहतर है। किसान ने बताया कि हालांकि नए खरीफ सीजन की खरीद शुरू हो चुकी है लेकिन उसके पिछले सीजन का ही धान अभी तक नहीं बिका है। उसके पास लगभग 220 बोरी धान है लेकिन सरकारी मंडी ने अभी तक इसकी खरीद नहीं की है। भोई ने जिलाधिकारी से कहा कि खेती ही उनके परिवार की आय का एकमात्र स्रोत है। उन्होंने कहा, मैंने जिले के अधिकारियों को कई पत्र लिखे लेकिन किसी ने भी मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया। कोई विकल्प नहीं होने के कारण मैंने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है।''

नीट प्रश्न पत्र लीक होने से 23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआः तेजस्वी यादव

पटना/भाषा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) रद्द किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ एक बार फिर खिलवाड़ हुआ है। यादव ने एक बयान जारी कर कहा कि बिहार और देश में प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं का अंतहीन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति सरकार की प्रशासनिक क्षमता, इच्छाशक्ति और सक्रियता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकारों में इतनी भी प्रशासनिक क्षमता और इच्छाशक्ति नहीं है कि एक सामान्य परीक्षा का आयोजन बिना पेपर लीक के सुनियोजित ढंग से कराया जा सके, या फिर यह भी कोई ऐसा दांव है जिससे जनता की परेशानी के बीच सत्ता को लाभ मिलता रहे।

टी20 प्रारूप के मानसिक पहलू से निपटना जरूरी है : साल्वी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रायपुर/भाषा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (आरसीबी) के गेंदबाजी कोच ओंकार साल्वी ने इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच से पहले मंगलवार को टी20 प्रारूप में सामंजस्य बैठाने की क्षमता और फैसले लेने की अहमियत पर जोर दिया। गत चैंपियन आरसीबी मौजूदा सत्र में 11 में से सात मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। तेज गेंदबाजी में टीम की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया है।

साल्वी ने कहा, ''हमारे पास इस प्रारूप के लिए जरूरी सभी तरह के कौशल वाले खिलाड़ी हैं लेकिन सबसे जरूरी बात मानसिक पहलू है। इस प्रारूप में बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। कभी-कभी पिच या हालात अनुकूल नहीं होते इसलिए एक गेंदबाज के तौर पर आप फैसले लेने में कैसे तेज हो सकते हैं इसी बारे में सारी बातें होती हैं और हम उसी तरह तैयारी करते हैं।'' इस सत्र में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह की पिचें देखने को मिल रही हैं इसलिए साल्वी ने सामंजस्य बैठाने की क्षमता पर जोर दिया।मुंबई इंडियन्स के खिलाफ मिली करीबी जीत पर साल्वी ने कहा कि ऐसी जीत से टीम का माहौल और समूह के अंदर भरोसा मजबूत होता है। साल्वी ने युवा तेज गेंदबाज रसिख सलाम की भी तारीफ की जिन्होंने अनुभव और सीख के जरिए प्रगति की है। साल्वी ने कहा, ''रसिख ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने अनुभवों और गलतियों से सीखा है। उन्हें पिछली टीमों से कुछ मुश्किलें भी आईं और उनसे कुछ सीखा भी और इन सभी चीजों ने उसे एक गेंदबाज के तौर पर बेहतर बनने में मदद की।''

हम सभी आशान्वित हैं, हमें पता है कि यह संभव है : वाटसन

रायपुर/भाषा। सहायक कोच शेन वाटसन ने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स धीमी शुरुआत के बाद अब एक टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उन्हें आईपीएल प्लेआफ में पहुंचने की पूरी उम्मीद है । नौ अंक लेकर आठवें स्थान पर काबिज केकेआर को प्लेआफ में पहुंचने के लिए बाकी सारे मैच जीतने होंगे । वाटसन ने गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु के खिलाफ मैच से पहले कहा ,'' ईमानदारी से कहूं तो हमने भविष्य के बारे में अभी बात नहीं की है ।'' उन्होंने कहा ,'' पिछले कुछ मैचों में खास तौर पर काफी प्रभावी प्रदर्शन रहा है और अब टीम सभी पहलुओं में अच्छा खेल रही है । हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और हमें पता है कि धीमी शुरुआत के बाद भी टीमें फाइनल में पहुंची हैं । आईपीएल का इतिहास यह दिखाता है और हमें पता है कि यह संभव है ।''

अदालत ने एनसी पर्वतीय स्वायत्त परिषद के दलबदल रोधी कानून को रद्द किया

गुवाहाटी/भाषा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एनसी पर्वतीय स्वायत्त परिषद द्वारा पारित दलबदल रोधी कानून को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि इसे बिना किसी अधिकार क्षेत्र के अधिनियमित किया गया था और यह असंवैधानिक है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की पीठ ने दीमा हसाओ जिले के कुछ निवासियों द्वारा दायर याचिका पर पारित किया जो परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है।

रिट याचिका में एनसी पर्वतीय स्वायत्त परिषद (42वां संशोधन) अधिनियम, 2017 के नियम 18ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी जिसमें राजनीतिक दलों से दल-बदल के आधार पर परिषद के निर्वाचित सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान था। नए नियम में यह प्रावधान किया गया था कि यदि कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल से संबंधित है और स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है; या यदि वह राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश या व्हिप के विपरीत परिषद में मतदान करता है या मतदान से परहेज करता है, तो वह सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

सुविचार

अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही न हो, पर अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बांग्लादेशी आगबबूला क्यों?

जब से पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनी है, बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की नींदें उड़ गई हैं। उन्होंने ढाका में जिस तरह विरोध प्रदर्शन करते हुए भारतीय नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां कीं, उससे स्पष्ट होता है कि वहां कट्टरपंथियों की बेचैनी बढ़ गई है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। अगर भारतीय नेता बांग्लादेश के साथ लगती सीमा पर बाड़ लगाने और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प. बंगाल सरकार बीएसएफ को जमीन सौंपने की दिशा में कदम उठा चुकी है। कानून का पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत को अधिकार है कि वह हर उस व्यक्ति को अपनी जमीन पर कदम रखने से रोके, जिसके पास आधिकारिक अनुमति नहीं है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार एम हुमायूं कबीर की यह टिप्पणी घुसपैठियों का खुला समर्थन है कि 'बांग्लादेश कंटीले तारों से नहीं डरता। जहां हमें बोलने की जरूरत होगी, हम बोलेंगे।' इसमें डरने-डराने की बात कहां से आ गई? बांग्लादेश भी अपनी जमीन पर बाड़ लगाने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोई व्यक्ति वहां गैर-कानूनी ढंग से कदम रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। पड़ोसी देश के वरिष्ठ अधिकारी यह कहकर घुसपैठियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमा सुरक्षा के मुद्दों पर ज्यादा मानवीय रवैया अपनाना होगा। भारत अब तक 'ज्यादा मानवीय रवैया' ही अपनाता रहा है। इसका नतीजा यह निकला कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के झुंड के झुंड हमारे देश में आकर मौज कर रहे हैं। क्या ज्यादा मानवीय रवैए का यह मतलब है कि किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठिए को इस ओर आने की पूरी आजादी दे दी जाए?

बांग्लादेशी सरकार और नागरिकों को समझना चाहिए कि अब भारत और ज्यादा घुसपैठियों का बोझ नहीं उठा सकता। भारत की अपनी जनसंख्या ही बहुत ज्यादा है। भारतीय नागरिकों तक मूलभूत सुविधाएं बड़ी मुश्किल से पहुंच रही हैं। ऐसे में बांग्लादेशियों का बोझ उठाना संभव नहीं है। इसलिए जो लोग बांग्लादेश की ओर से घुसपैठ करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, जो बांग्लादेशी गलत तरीके से पहले यहां आकर बस चुके हैं, उन्हें वापस स्वदेश भेज देना चाहिए। बांग्लादेशियों के लिए रोटी, रोजगार और आवास का प्रबंध करना भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें बांग्लादेशी सरकार से इनकी मांग करनी चाहिए। इस पड़ोसी देश में जो लोग पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत से आगबबूला हो रहे हैं, उन्हें अपने घर के हालात पर ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है। कई इलाकों में ईंधन की भारी किल्लत हो गई है। उसे भारत को धन्यवाद कहना चाहिए कि मुश्किल समय में मदद का हाथ बढ़ाया, अन्यथा बांग्लादेश में औद्योगिक गतिविधियां पूरी तरह ठप पड़ जातीं। अगर बांग्लादेशी सरकार यह चाहती है कि घुसपैठियों और तस्करों की निर्बाध आवाजाही रहे, तो अब ये गतिविधियां नहीं चलेंगी। हाल में बीएसएफ ने दो बांग्लादेशी तस्करों को ढेर किया था। ऐसी कार्रवाई जरूरी है। घुसपैठ और तस्करी जैसे काम स्थानीय मददगारों के बगैर नहीं हो सकते। सरहदी इलाकों में ऐसे लोगों का मजबूत नेटवर्क होता है। पुलिस, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों को मिलकर इस नेटवर्क को तोड़ना होगा। जो लोग इसमें लिप्त पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। जब सरहद पार यह बात समझ में आ जाएगी कि 'घुसपैठ करना बहुत महंगा पड़ सकता है' और 'तस्करी करने पर जान गंवानी पड़ सकती है', तो ये गतिविधियां धीरे-धीरे बंद हो जाएंगी।

ट्वीटर टॉक

पेपर माफिया ने पूरे देश में शिक्षा और परीक्षा दोनों पर कब्ज़ा कर लिया है। एक ऐसे देश में शिक्षा और परीक्षाएं जो पेपर माफिया का शिकार हो रही हैं, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटक रहा है। नीट पेपर लीक के बाद, इस पेपर को कैंसिल करके नए सिरे से क्यों नहीं कराया जा रहा है?

-रणदीपसिंह सुरजेवाला

वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगले नेवल स्टाफ चीफ के तौर पर अपॉइंट होने पर बहुत-बहुत बधाई।बेंगलूरु के एक गर्वित बेटे और सैनिक स्कूल बीजापुर के एल्युम्नस, उन्होंने इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले स्कूल के पहले कैडेट के रूप में इतिहास रच दिया है।

-सिद्दरामय्या

आज गुवाहाटी में हुए असम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, मुझे इगझ परिवार के टॉप लीडरशिप और सीनियर नेताओं से गर्मजोशी से मिलने का मौका मिला। देशहित से जुड़े कई ज़रूरी टॉपिक पर प्रेरणा देने वाला गाइडेंस मिला।

-दिया कुमारी

प्रेरक प्रसंग

आत्मविश्वास में सफलता

एक युवक ने स्वामी विवेकानंद से शिकायत की कि वह जीवन में बार-बार डर और संकोच का अनुभव करता है, इसलिए किसी बड़े कार्य की शुरुआत ही नहीं कर पाता। विवेकानंद उसे नदी किनारे ले गए, जहां कुछ लोग नाव में बैठने से डर रहे थे क्योंकि पानी का बहाव तेज था। तभी एक वृद्ध मल्लाह शांतिपूर्वक नाव लेकर नदी पार कर गया। विवेकानंद ने युवक से पूछा, 'उसमें और इन लोगों में क्या अंतर है?' युवक बोला, 'उसे अपने कौशल पर विश्वास है।' तब विवेकानंद ने कहा, 'मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास है; भय तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते।' उन्होंने समझाया कि साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। यदि व्यक्ति अपनी शक्ति पर विश्वास करना सीख ले, तो कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं।

सामयिक

ऊर्जा संकट में सरकार बनी ढाल

कुमकुम शर्मा

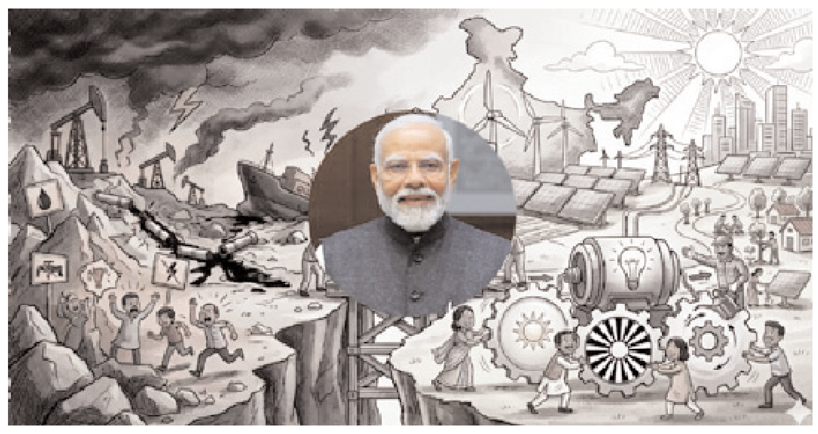

धवैश्विक युद्ध और होर्मुज संकट का असर आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। युद्ध की लपटें केवल सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। उनका असर हर घर की रसोई, हर वाहन के पहिए और हर परिवार के बजट तक पहुंच चुका है। कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें इतिहास के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगीं, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी और सरकारें अपने नागरिकों के गुस्से का सामना करने को मजबूर हो गईं।

इसी उथल-पुथल के बीच आज युद्ध के लगभग 11 सप्ताह बीतने पर भी भारत में जीवन की सामान्य गति बनी रही, करोड़ों परिवारों के चूल्हे जलते रहे, गाड़ियां चलती रहीं। यह अपने आप नहीं हुआ। इसके पीछे एक ऐसी नीति, ऐसी तैयारी और ऐसी संवेदनशील सोच थी, जिसने वैश्विक तूफान के सामने भारत के नागरिकों को ढाल बनकर संरक्षण दिया। जब दुनिया ऊर्जा संकट की आग में झुलस रही थी, तब मोदी सरकार एक संरक्षक की तरह अपने नागरिकों के साथ खड़ी रही। जैसे द्वापर में भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को बचाया था, वैसे ही इस कठिन समय में सरकार ने बढ़ती वैश्विक कीमतों और आर्थिक दबाव का बड़ा हिस्सा स्वयं अपने ऊपर उठाया, ताकि उसका बोझ सीधे जनता की थाली, रसोई और जेब तक न पहुंचे।

यही कारण है कि आज यह संकट केवल आर्थिक प्रबंधन की कहानी नहीं, बल्कि संवेदनशील शासन, दूरदर्शी नेतृत्व और नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व की मिसाल बन चुका है। दुनियाभर में बढ़ती कीमतों का बोझ सीधे जनता पर डाल देना सबसे आसान रास्ता था और कई देशों ने ऐसा ही किया, लेकिन भारत ने यह रास्ता नहीं चुना। मोदी सरकार ने स्वयं भारी आर्थिक दबाव सहा ताकि आम आदमी की रसोई और रोजमर्रा की जिंदगी पर कम से कम असर पड़े। सरकार ने लगभग पेट्रोल पर 24 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का भार वहन किया। 28 फरवरी के बाद से वैश्विक स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। यूरोप और एशिया के कई देशों में पेट्रोल 30 से लेकर 35 प्रतिशत तक महंगा हुआ, जबकि भारत में कोई बदलाव नहीं किया गया। हांगकांग में आज पेट्रोल सबसे महंगा है। वहां एक लीटर की कीमत लगभग 295 रुपए पहुंच गई है, जो 28 फरवरी के बाद 25 प्रतिशत बढ़ी है। सिंगापुर में दाम 30 प्रतिशत बढ़कर करीब 240 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। नीदरलैंड में पेट्रोल 225 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, जो 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। युद्धग्रस्त इजराइल में पेट्रोल 30 प्रतिशत महंगा होकर 185 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं भारत में अब भी पेट्रोल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर है।

> **युद्ध अब भी जारी है। आने वाले समय में कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं, लेकिन देश को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब पूरी दुनिया दबाव में थी, तब भारत सरकार ने अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ा। उसने एक अभिभावक की तरह जिम्मेदारी निभाई। सरकारें केवल योजनाओं और घोषणाओं से बड़ी नहीं बनतीं, बल्कि कठिन समय में अपने लोगों के साथ खड़े होने से बड़ी बनती हैं।**

प्रतिदिन लगभग 1,000 करोड़ का घाटा उठाना कोई साधारण बात नहीं है। अब तक लगभग 68,000 करोड़ का बोझ सरकार और तेल कंपनियों ने अपने ऊपर लिया है। यह आंकड़ा उस संवेदनशील सोच का प्रमाण है, जिसमें मोदी सरकार ने पहले नागरिकों की चिंता की और बाद में अपने खजाने की। सोचिए, यदि यही संकट बिना तैयारी के आया होता तो क्या स्थिति होती? रसोई गैस महंगी होती, परिवहन लागत बढ़ती, महंगाई हर घर तक पहुंचती और मध्यम वर्ग से लेकर गरीब तक का बजट डगमगा जाता।

साल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आते ही स्थितियां बदलनी शुरू हुई थीं। पिछले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो दूरदर्शी तैयारी की गई, वही आज देश की ढाल बनकर खड़ी है। तेल भंडार तैयार किए गए, एथनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाई गई, वैकल्पिक ईंधन नेटवर्क विकसित हुआ और रिफाइनिंग क्षमता का विस्तार शुरू हुआ। वैकल्पिक ईंधन के माध्यम से एलपीजी की मांग को 70 से 75 हजार टन प्रतिदिन कम किया गया। यह केवल इसलिए संभव हुआ, क्योंकि पीएनजी, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल और बायोमास की वैकल्पिक अवसंरचना संकट से पहले से तैयार थी। जापान और दक्षिण कोरिया के बाद भारत ही ऐसा देश है, जो 30-दिवसीय एलपीजी भंडार की योजना बना रहा है।

आज भारत के पास 5.33 मिलियन टन का रणनीतिक तेल भंडार है और दूसरे चरण के तहत चंडीखोल, पादुर और बीकानेर में अतिरिक्त भंडारण क्षमता तैयार की जा रही है। ये केवल परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि भविष्य के संकटों से देशवासियों को सुरक्षित रखने की तैयारी है। एथनॉल मिश्रण की नीति ने भी इस कठिन समय में देश को बड़ी राहत दी। 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग के कारण भारत विदेशी मुद्रा की भारी बचत कर पा रहा है। संकट के दौरान वैकल्पिक ईंधन व्यवस्था के जरिए एलपीजी की मांग में प्रतिदिन 70 से 75 हजार टन तक कमी लाई गई। ये कदम बताते हैं कि सरकार ने केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी सुरक्षा का रास्ता तैयार किया है।

युद्ध अब भी जारी है। आने वाले समय में कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं, लेकिन देश को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब पूरी दुनिया दबाव में थी, तब भारत सरकार ने अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ा। उसने एक अभिभावक की तरह जिम्मेदारी निभाई। सरकारें केवल योजनाओं और घोषणाओं से बड़ी नहीं बनतीं, बल्कि कठिन समय में अपने लोगों के साथ खड़े होने से बड़ी बनती हैं।

इस वैश्विक संकट के दौर में भारत ने यह करके दिखाया है। यही कारण है कि आज देश का आम नागरिक सिर्फ राहत महसूस नहीं कर रहा, बल्कि उसके मन में यह भरोसा भी मजबूत हुआ है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, देश उसके साथ खड़ा है। हालांकि यह संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। समय की मांग यह भी है कि देश के नागरिक आने वाली चुनौतियों के प्रति सजग, संयमित और तैयार रहें। नागरिकों का कर्तव्य है कि ऊर्जा का इस्तेमाल किफायत से करें। वैश्विक संकट के बीच ढाल बनी भारत सरकार का धैर्यपूर्वक साथ दें। (हिफी)

नजरिया

घुसपैठियों की समस्या से त्रस्त पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद विदेशी घुसपैठिओं के चेहरे उतरने लगे हैं, क्योंकि अब इन विदेशी घुसपैठियों को सहन नहीं किया जाएगा। अब उनको बाहर जाना ही होगा। भाजपा की सरकार ही इनको बाहर निकलेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे हैं। यहां यह कहना भी उचित होगा कि भाजपा ने केवल घुसपैठियों को बाहर निकालने की ही बात की है, भारत के मुसलमानों की नहीं, लेकिन विपक्ष और खासकर तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि सारे मुस्लिमों पर इसका प्रभाव होगा।

अब घुसपैठ से मुक्त होगा बंगाल

सुरेश हिंदुस्तानी
मोबाइल : 9425101815

पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तौर पर शुभेन्दु अधिकारी ने शासन की बागडोर संभाल ली है। भाजपा का यह स्पष्ट नारा रहा है कि वह विदेशी घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। इसलिए पश्चिम बंगाल के जनादेश में इस पर अब जनता की मुहर भी लग गई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टिकरण को बढ़ावा देकर अपने शासन का संचालन किया। इसमें बांग्लादेश के घुसपैठियों का भी समर्थन भी शामिल रहा। अब भाजपा की सरकार बनने के बाद यह तय हो चुका है कि अब पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से लगी हुई सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगी और एक बड़ी समस्या से छुटकारा भी मिलेगा। इससे यह भी आशय निकलता है कि सबका साथ और सबका विकास वाली राजनीतिक अवधारणा को स्वीकार किया जाने लगा है। देश में इसी प्रकार की राजनीति की आवश्यकता है। क्योंकि राजनीतिक दलों ने आज देश में रहने वाले समाज के बीच इतना भेद पैदा कर दिया है कि कई जगह समाज बंधु एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। हिन्दू और मुसलमान समाज के ही हिस्से हैं, इसलिए इनको अलग अलग देखने की राजनीति नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत देश के कुछ राजनीतिक दलों का आधार ही मुस्लिम वोट हैं। जबकि यह भी सही है कि तुष्टिकरण से किसी का भला न तो हुआ है और न ही होगा।

लम्बे समय से पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का अप्रत्याशित रूप से बढ़ना कई प्रकार के सवाल खड़ा करता रहा है। इसके पीछे बांग्लादेश से आए घुसपैठिए भी एक बड़ा कारण है। इस समस्या से बंगाल ही नहीं, असम भी प्रभावित है, लेकिन अच्छी बात यह है कि विपक्षी राजनीतिक दलों को यह समस्या दिखाई नहीं देती। असम और पश्चिम बंगाल की जनता इस घुसपैठ के विरोध में खड़ी हो गई है, इसलिए इस बार का जनादेश भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोध में आया। इसी के चलते असम में भाजपा सरकार का पुनः बनना और पश्चिम बंगाल में एक नए राजनीतिक उदय के साथ सत्तारूढ़ होना इसी बात का परिचायक है कि भाजपा ही नहीं, जनता भी देश से घुसपैठियों को निकालने का मन बना चुकी है। सुनने में यह भी आ रहा है जो बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करके आए, वे अपने देश वापस जाने का मानस बना चुके हैं। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल घुसपैठ की समस्या से मुक्त हो जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में प्रारंभ से ही इस बात पर जोर दिया था कि वह विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ है। भाजपा के नेताओं के भाषण भी इसी पर केंद्रित रहते थे। इस मुद्दे पर भाजपा को जनता का भी समर्थन मिला और जनता ने भाजपा को बहुमत दे दिया। इसके अलावा ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने जो कार्य किए, वह कहीं न कहीं हिन्दू समाज को नीचा दिखाने वाले ही थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता शायद इस बात को भूल गए कि बहुसंख्यक समाज को नकारने की राजनीति एक प्रकार से उसके लिए सत्ता से अलग होने की तस्वीर पेश कर सकती है।

पश्चिम बंगाल घुसपैठ की समस्या से बहुत प्रभावित हुए हैं। यहां पर अप्रत्याशित रूप से ज़मीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। कई जगह अचानक ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनते जा रहे हैं। जिनमें मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा आदि है। यह तीनों जिले बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। इसके चलते बंगाल में अपराध भी बहुत होने लगे हैं। इसका कारण यही माना जा रहा है कि जो व्यक्ति घुसपैठ करके आए हैं, उनके सामने रोजगार का संकट है। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति गलत कार्य भी करने लगता है। इससे की दशा और दिशा भी ख़राब हो रही है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रास्ते कई बांग्लादेशी नागरिक घुसपैठ करते रहे हैं। स्थानीय नागरिकों की मदद से वे सभी अपने आशियाने भी बना रहे थे, इनके ज्यादातर आशियाने अवैध कब्ज़ा करके ही बने हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के समय इनको पर्याप्त संरक्षण भी मिला। उल्लेखनीय है जिन क्षेत्रों में मुस्लिमों की जनसंख्या अचानक बढ़ी है, वे सभी तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्र रहे हैं। इन क्षेत्रों में हिन्दू समाज का कोई भी व्यक्ति जाने से डरता है। सवाल यह है कि यह डर किसने पैदा किया और इसको संरक्षण देने वाले कौन हैं। तृणमूल कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राह पर चलते हुए इनको ताकत देने का काम किया। और यही उसकी हार का कारण भी बना।

अब पश्चिम बंगाल का राजनीतिक दृश्य परिवर्तित हो चुका है। जिन्होंने लम्बे समय तक अमानुषिक अत्याचार सहन किए, वे सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन भाजपा को यह सत्ता ऐसे ही नही मिल गई। उसके सैकड़ों कार्यकर्ता का बलिदान इस जीत के नींव के पत्थर बने। चुनाव के बाद शुभेन्दु अधिकारी के निजी सहायक देवनाथ की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह कार्य प्रशिक्षित अपराधियों ने किया। संभावना इस बात की भी है कि घटना के बाद ये बांग्लादेश भाग चुके हैं। इसे राजनीतिक हत्या के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसके आरोप तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लग रहे हैं।

घुसपैठियों की समस्या से त्रस्त पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद विदेशी घुसपैठिओं के चेहरे उतरने लगे हैं, क्योंकि अब इन विदेशी घुसपैठियों को सहन नहीं किया जाएगा। अब उनको बाहर जाना ही होगा। भाजपा की सरकार ही इनको बाहर निकलेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे हैं। यहां यह कहना भी उचित होगा कि भाजपा ने केवल घुसपैठियों को बाहर निकालने की ही बात की है, भारत के मुसलमानों की नहीं, लेकिन विपक्ष और खासकर तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि सारे मुस्लिमों पर इसका प्रभाव होगा। विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना सभी चाहते हैं, विपक्ष को इस मुद्दे पर भाजपा का साथ देना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय हित की बात है।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

पाकिस्तान ने हवाई अड्डे पर ईरानी विमानों को जगह दिए जाने की खबर को भ्रामक बताया

इस्लामाबाद/भाषा

पाकिस्तान ने अमेरिकी मीडिया की उस खबर कोभ्रामक बताते हुए मंगलवार को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि इस्लामाबाद ने ईरानी सैन्य विमानों को अमेरिकी हवाई हमलों से बचाने के लिए अपने हवाई अड्डों में जगह दी थी। विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि देश में वर्तमान में मौजूद ईरानी विमान युद्धविराम अवधि के दौरान उस समय आया था जब अमेरिका-ईरान शांति वार्ता का पहला दौर जारी था और उनका किसी भी सैन्य आपात स्थिति या किसी सुरक्षा-संबंधी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है।

'सीबीएस न्यूज' ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक खबर में कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध को समाप्त कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने ईरानी सैन्य विमानों को अमेरिकी हवाई हमलों से बचाने के लिए अपने हवाई अड्डों में जगह दी थी। 'सीबीएस न्यूज' ने खबर में दावा किया कि अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ युद्धविराम की घोषणा के कुछ दिनों बाद तेहरान ने कई विमान रावलपिंडी के निकट स्थित नूर खान एयरबेस पर भेज दिए थे। खबर में दावा किया गया है,इनमें ईरानी वायु सेना का आरसी-130 भी शामिल था, जो लॉकहीड सी-130 हरक्यूलिस सामरिक परिवहन विमान का एक टोही और खुफिया जानकारी जुटाने वाला संस्करण है।

अपने बयान में विदेश कार्यालय ने 'सीबीएस न्यूज' की खबर कोभ्रामक और सनसनीखेज बताते हुए स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। इसमें कहा गया है,इस तरह की बातें क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए जारी प्रयासों को कमजोर करने के उद्देश्य से कही जा रही हैं।

बयान में कहा गया है,युद्धविराम के बाद और इस्लामाबाद वार्ता के पहले दौर के दौरान, वार्ता प्रक्रिया से जुड़े राजनयिक कर्मियों, सुरक्षा टीमों और प्रशासनिक कर्मचारियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए ईरान और अमेरिका से कई विमान पाकिस्तान पहुंचे थे। इसमें कहा गया है,पाकिस्तान ने तनाव कम करने के लिए लगातार एक निष्पक्ष, रचनात्मक और जिम्मेदार मध्यस्थ के रूप में कार्य किया है। इस भूमिका के अनुरूप, पाकिस्तान ने आवश्यकतानुसार नियमित रसद एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान की है, साथ ही सभी संबंधित पक्षों के साथ पूर्ण पारदर्शिता और नियमित संचार बनाए रखा है। बयान में कहा गया है,पाकिस्तान संवाद को बढ़ावा देने, तनाव कम करने और क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए रिपब्लिकन पार्टी के सांसद लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका-ईरान युद्ध को समाप्त कराने के लिए मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका पर फिर से विचार करने की जरूरत पर जोर दिया।

कार्यभार

पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल मंगलवार को कोलकाता के विकास भवन में महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण और नगर निगम मामलों के विभागों का कार्यभार संभालते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली डायरी पकड़े हुए।

'इंस्पेक्टर अविनाश' में विजुअल परफेक्शन से ज्यादा भावनात्मक ईमानदारी जरूरी : उर्वशी रौतेला

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला एक बार फिर वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' के नए सीजन में पूनम मिश्रा के किरदार में नजर आने वाली हैं। इस बीच उर्वशी ने अपने किरदार और एक्टिंग को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पब्लिक इमेज हमेशा ग्लैमर से जुड़ी रही है, लेकिन 'इंस्पेक्टर अविनाश' जैसे प्रोजेक्टस में दिखावे से ज्यादा सच्ची भावनाओं की जरूरत होती है। उर्वशी ने आईएएनएस से बताया कि एक कलाकार के तौर पर आगे बढ़ने के लिए 'परफॉर्मेंस वैनिटी' यानी

परफेक्ट दिखने की सोच को छोड़ना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने कहा, लोग अक्सर मुझसे हर फ्रेम, हर एक्सप्रेशन और हर पल में परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, क्योंकि मेरी छवि ग्लैमरस रही है। लेकिन 'इंस्पेक्टर अविनाश' जैसे प्रोजेक्ट विजुअल परफेक्शन से ज्यादा भावनात्मक ईमानदारी मांगती हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि इस किरदार के लिए उन्होंने खुद को ज्यादा 'प्रेजेंट' रखने पर ध्यान दिया उर्वशी ने कहा, असल जिंदगी में मुश्किल हालात से गुजर रहे लोग यह नहीं सोचते कि वे कैसे दिख रहे हैं। वे सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, हालात से जूझ रहे होते हैं और भावनाओं को महसूस कर रहे होते हैं। एक अभिनेता के तौर पर इस सच्चाई को समझना मेरे लिए बेहद जरूरी था।

पश्चिम एशिया संघर्ष न सुलझा तो ऊर्जा संकट बढ़ेगा: फारूक अब्दुल्ला

श्रीनगर/भाषा। नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि अगर पश्चिम एशिया का संघर्ष जल्द नहीं सुलझा तो देश ऊर्जा संकट की ओर बढ़ता जायेगा।

अब्दुल्ला ने यहां पत्रकारों से कहा,''संकट हमारे करीब आ रहा है ईंधन संकट, गैस संकट। हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ईंधन बचाने के लिए स्कूलों को ऑनलाइन तरीके में ले जाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा,लेकिन सभी विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा और इस संबंध में कुछ करना होगा क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है।

एक सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने कहा कि अर्थव्यवस्था गंभीर स्थिति में है। उन्होंने कहा,हां, अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से गंभीर संकट में है। अगर यह ईरान-अमेरिका संघर्ष जल्द खत्म नहीं हुआ तो भगवान ही मालिक है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ईंधन की बचत और आयात में कमी करने का आह्वान किया था क्योंकि वैश्विक ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने सोने की खरीद में भी संयम बरतने का आग्रह किया था । शराब पर प्रतिबंध लगाने की पीडीपी की मांग पर अब्दुल्ला ने कहा कि वह महज आलोचना के लिए सरकार की आलोचना कर रही है, क्योंकि उसके पास उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उन्होंने पीडीपी का नाम लिए बगैर सवाल किया कि जब शराब की दुकानें खोली जा रहा थी, तब वे क्यों चुप थे। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को शराब पर प्रतिबंध से होने वाली राजस्व हानि के लिए कोई राहत देती है तो राज्य सरकार मद्यनिषेध लागू करने में एक क्षण भी नहीं गंवाएगी।

'डीडीएलजे' के मशहूर दृश्य की शूटिंग वाले रेलवे स्टेशन को पर्यटन स्थल बनाने का अनुपम खेर का अनुरोध

नयी दिल्ली/भाषा

अभिनेता अनुपम खेर उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर पुरानी यादें ताजा कीं जहां फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के 'मशहूर' दृश्य की शूटिंग हुई थी। खेर ने सरकार से उस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की अपील की। फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' 1995 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन आदित्य चोपड़ा ने किया था। फिल्म में काजोल और शाहरुख खान ने क्रमशः सिमरन और राज की भूमिका निभाई थी, जो यूरोप यात्रा के दौरान मिलते हैं और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। हालांकि, राज को जब पता चलता है कि सिमरन की शादी कहीं और तय हो चुकी है, तो वह उसे और उसके पिता को मनाने के लिए भारत पहुंचता है।

'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल है। इसकी कहानी, कलाकारों के अभिनय और गीतों को काफी सराहना मिली और यह फिल्म रिलीज के दशकों बाद भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं।

फिल्म का ट्रेन वाला दृश्य, जिसमें राज अपना हाथ बढ़ाता है और सिमरन भागते हुए ट्रेन की ओर आती है, वर्षों से दर्शकों की स्मृतियों में बसा हुआ है। इस दृश्य को बाद में कई फिल्मों में दोहराया भी गया। खेर ने फिल्म में शाहरुख खान के पिता धर्मवीर की भूमिका निभाई थी। उन्होंने सोमवार को अपने 'इंस्टाग्राम अकाउंट' पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह अप्टा रेलवे स्टेशन पर दिखे।

अभिनेता ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि दुनिया भर का हर भारतीय फिल्म के उस ट्रेन वाले दृश्य को जानता है और याद करता है। वह वीडियो में कहते सुनाई देते हैं, मैं एक रेलवे स्टेशन पर आया हूं। यहां एक प्रतिष्ठित फिल्म का प्रतिष्ठित दृश्य शूट किया गया था। यह भारतीय सिनेमा के इतिहास का हिस्सा है, जिसे दुनिया भर के हर भारतीय ने देखा और याद रखा होगा।

यह दृश्य 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का है। यह वैसा ही है जैसे 'द गॉडफादर' के किसी दृश्य के लिए सिसिली जाना। ये सभी जगह प्रतिष्ठित हैं। मुझे इस प्रतिष्ठित फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए यश जी (यश चोपड़ा) और आदि (आदित्य चोपड़ा) का आभारी हूं। अभिनेता ने कैप्शन में लिखा कि शूटिंग के दौरान कलाकारों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। उन्होंने सरकार से इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की अपील भी की।

सुकेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जैकलीन फर्नांडीस के सरकारी गवाह बनने का किया विरोध

नई दिल्ली/एजेन्सी

महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी सरकारी गवाह (अप्रूवर) बनने की अर्जी का कड़ा विरोध किया है। दूसरी ओर, पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीस के वकील को ईडी के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अगली सुनवाई 12 मई को होगी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया था और उनका आचरण संतोषजनक नहीं रहा था। उन्होंने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयानों में पूर्ण और सही

खुलासा करने में लगातार विफलता दिखाई।

ईडी ने कहा कि जैकलीन फर्नांडीस ने सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास की जानकारी होने के बाद भी उनके साथ नियमित और लगातार संपर्क बनाए रखा, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग से होने वाली अपराध की आय में से जैकलीन को गिफ्ट और अन्य सामान दिलाए। सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। इस हाई-प्रोफाइल केस में जैकलीन फर्नांडिस का नाम तब सामने आया था, जब जांच एजेंसी ने दावा किया कि सुकेश ने ठगी के पैसों से जैकलीन को कई महंगे गिफ्टस दिए थे। इसी आधार पर ईडी ने उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया था।

जैकलीन ने हाल ही में कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह इच्छा जताई थी कि वह इस मामले में सरकारी गवाह बनना चाहती हैं और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी ने उनके इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फिलहाल उनकी अर्जी को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार नहीं दिखता।

रैली

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भाजपा की 'आक्रोश रैली' के दौरान भाषण दिया। झारखंड में कथित पानी और बिजली संकट को लेकर मंगलवार रांची में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया।

उल्टे होकर शिल्पा शेट्टी ने बताए योग के फायदे

जयपुर/एजेन्सी

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की उन डीवास में शुमार है, जो अपनी सेहत को लेकर काफी जागरुक रहती हैं। उन्होंने सोमवार को योग करने के साथ-साथ महिलाओं को आवश्यक जानकारी दी। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपने वर्कआउट सेशन का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में शिल्पा उल्टा योगा पोज करती हुई दिखाई दे रही हैं। अभिनेत्री बहुत ही बारीकी और कंट्रोल के साथ यह पोज करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के जरिए उन्होंने बताया कि महिलाओं को अपने पीरियड्स के दौरान कुछ खास एक्सरसाइज और उल्टे पोज करने से बचना चाहिए। शिल्पा ने वीडियो शेयर कर लिखा, हर योग मुद्रा आपको शरीर और मन दोनों से मजबूत और लचीला बनाता है। उन्होंने पोज के फायदे बताते हुए लिखा, इसके नियमित अभ्यास से दिमाग में रक्त संचार बेहतर होता है, थायरॉइड और पैराथायरॉइड ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। साथ ही, तनाव और चिंता कम करने में मदद मिलती है। पाचन बेहतर होता है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है। गर्दन, कंधे और पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं।

अभिनेत्री ने पोस्ट के अंत में योगासन के फायदे बताने के बाद इससे जुड़ी सावधानियों पर बताई। उन्होंने लिखा, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, ग्लूकोमा, गर्दन दर्द या स्लिप डिस्क की समस्या है, तो यह आसन न करें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान इस आसन से बचें। आयुष मंत्रालय के सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार, 'उल्टा योगा पोज' या इनवर्जन के अंतर्गत मुख्य रूप से सर्वांगासन और विपरीतकरणी को शामिल किया जाता है। ये आसन शरीर में रक्त के संचार को सिर की ओर बढ़ाते हैं। शुरुआती योगाभ्यासकर्ताओं को इस आसन को किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करना चाहिए। इसे नियमित तौर पर करने से पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर चिंता कम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। साथ ही, शरीर में स्फूर्ति और ताजगी लाता है।

प्रदर्शन

नई दिल्ली में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य और समर्थक मंगलवार को नई दिल्ली में कथित नीट-यूजी पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए।

सलमान खान की सलाह से लेकर अनीस बज्मी की मंजूरी तक: ऐसे हुई कुब्रा सैत की फिल्म 'रेडी' से बड़ी शुरुआत

मुंबई/एजेन्सी

कुब्रा सैत आज भले ही 'सैक्रेड गेम्स' में अपने यादगार किरदार 'कुकू' के लिए जानी जाती हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह मुंबई में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। हाल ही में एक वीडियो में अभिनेत्री ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें किस तरह फ़िल्म 'रेडी' में अपना पहला मौका मिला। इस फिल्म का निर्देशन अनीस बज़्मी ने किया था और इसमें मुख्य भूमिका में थे सलमान खान। कुब्रा ने बताया कि उन्होंने इस रोल के लिए एक छोटी ब्लैक ड्रेस पहनकर ऑडिशन दिया था और बेसब्री से अनीस बज्मी के ऑफिस में उनके अप्रूवल का इंतजार कर रही थीं। शुरुआत में फिल्म में उनके किरदार के लिए कोई डायलॉग नहीं था और उन्हें एक मेड का रोल दिया गया था। लेकिन बाद में सलमान खान ने सुझाव दिया कि उनके किरदार को थोड़ा मजेदार बनाया जाए और वह टूटी-फूटी अंग्रेज़ी बोले। अनीस बज्मी को सलमान खान यह आइडिया काफी पसंद आया और इसी वजह से कुब्रा के किरदार में डायलॉग्स जोड़े गए।

यही छोटा-सा बदलाव उनके लिए स्क्रीन पर यादगार पल बन गया। अपने अनुभव को साझा करते हुए कुब्रा ने कहा,यह वही ऑडिशन था जिसमें मैंने एक छोटी ब्लैक ड्रेस पहनी थी और अनीस बज्मी सर के अप्रूवल का इंतजार कर रही थी। मैं फिल्म 'रेडी' में एक मेड का किरदार निभाने वाली थी और इसे लेकर बहुत उत्साहित थी। इस फिल्म को करते समय मेरे अंदर ग़ज़ब का आत्मविश्वास था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कोई फिल्म नहीं की थी। शुरुआत में मेरे किरदार के कोई डायलॉग भी नहीं थे। लेकिन फिर सलमान खान ने कहा कि क्यों न इस मेड को टूटी-फूटी अंग्रेज़ी बोलने वाला बनाया जाए। अनीस सर को यह आइडिया पसंद आया और इस तरह मुझे फिल्म में डायलॉग मिले। कुब्रा आगे बताती हैं, हालांकि उस दौरान हर किसी ने मुझसे कहा कि मैं पागल हूं, अधीर हूं, जो 'रेडी' में सुनैना

कपूर का इतना छोटा रोल कर रही हूं। लेकिन अगर मैंने 'रेडी' नहीं की होती, अगर मैं इतनी 'पागल' नहीं होती, तो शायद मैं कभी 'कुकू' नहीं बन पाती। कभी मत कहो कि कोई रोल छोटा है। छोटे रोल नहीं होते, छोटे कलाकार होते हैं।

कुब्रा ने खुलकर बताया कि उनके आसपास कई लोगों को लगता था कि इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म में छोटा किरदार स्वीकार करना सही फैसला नहीं है। लेकिन अभिनेत्री का मानना है कि यही फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उनके अनुसार, अगर उन्होंने उस समय यह मौका नहीं लिया होता, तो शायद उन्हें आगे चलकर 'कुकू' जैसा आइकॉनिक किरदार निभाने का अवसर भी नहीं मिलता। अपनी कहानी के अंत में कुब्रा ने उभरते कलाकारों को प्रेरित करते हुए कहा कि किसी भी भूमिका को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक दशक बाद भी वह 'रेडी' को अपने अभिनय सफर का सबसे अहम पड़ाव मानती हैं।

'ग्लोरी' के लिए पुलकित सम्राट क्यों थे परफेक्ट चॉइस?

मुंबई /एजेन्सी

'ग्लोरी' सीरीज़ में जहां पुलकित सम्राट के अभिनय से दर्शक प्रभावित हैं, वहीं उससे ज़्यादा प्रभावित पुलकित को 'ग्लोरी' में निर्देशित करनेवाले फिल्मकार करण अंशुमन हैं। पुलकित के परफॉर्मेंस और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे फिल्मकार करण अंशुमन का कहना है कि पुलकित उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिन्होंने इस सीरीज़ की कठिन तैयारी और पूरी प्रक्रिया के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले ये जोड़ी 'बैंगिस्तान' में भी साथ काम कर चुकी है। करण की मानें तो यही वजह है कि उन्होंने 'ग्लोरी' के लिए पुलकित को चुना क्योंकि उन्हें पता था कि अभिनेता इस किरदार में भावनात्मक ईमानदारी और पूरी मेहनत दोनों लेकर आएंगे। पुलकित को इस भूमिका के लिए चुनने के बारे में बात करते हुए करण ने कहा, मुझे लगता है कि हमने उन्हें इसलिए अप्रोच किया था, क्योंकि मुझे ऐसा इंसान चाहिए था जो इस किरदार के लिए अपना सब कुछ दे सके। मुझे यह भी पता था कि उनके लिए यह एक बेहद नया और ताज़गी भरा बदलाव होगा और वह इस किरदार को पूरी तरह अपनाएंगे और पुलकित ने बिल्कुल वैसा ही किया भी।

बॉक्सिंग ट्रेनिंग पर बात करते हुए करण ने यह भी कहा कि 'ग्लोरी' सिर्फ बॉक्सिंग और एक्शन ट्रेनिंग के जरिए शारीरिक बदलाव की मांग नहीं करती थी, बल्कि इसमें भावनात्मक गहराई, धैर्य और रचनात्मक प्रक्रिया में पूरी भागीदारी भी जरूरी थी, जो उन्हें पुलकित में स्वाभाविक रूप से दिखाई दी। करण कहते हैं, आज की तेज़ रफ्तार इंडस्ट्री में ऐसे कलाकार बहुत कम मिलते हैं, जो तैयारी के लिए इतना लंबा समय दे सकें। ज़्यादातर स्टार्स के पास इतना समय ही नहीं होता कि वे हर चीज़ की डिटेल में जाकर तैयारी कर पाएं। सच कहूँ तो मुझे कोई ऐसा चाहिए था

जो 247 इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। ऐसे में पुलकित ने रिहर्सल, वर्कशॉप और स्क्रिप्ट रीडिंग्स में खुद को पूरी तरह झोंक दिया और सेट पर जाने से पहले किरदार के हर पहलू को समझने में अनगिनत घंटे लगाए, जो वाकई काबिले तारीफ़ है। हालांकि ऐसा नहीं था कि हमने एक बार स्क्रिप्ट पढ़ी और आगे बढ़ गए। हमने उसे बार-बार किया।

यह पुलकित की ही ईमानदारी है, जिसने पूरी प्रक्रिया को और बेहतर बना दिया। यही वजह है कि पुलकित के एक्शन सीक्वेंस और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जितनी चर्चा है, उतनी ही चर्चा पुलकित के भावनात्मक और संवेदनशील दृश्यों की भी है, जिसने सबसे गहरा असर छोड़ा है। तैयारी के महत्व पर जोर देते हुए करण ने यह भी कहा कि जिस दबाव वाले माहौल में हम शूटिंग करते हैं, उसमें चीज़ों को सही करना आसान नहीं होता।

आपको पहले से पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है, जिससे शूटिंग के बाद संतुष्टि हो कि जो आपने सोचा था, वैसा ही हुआ। वैसे तो सभी ने बेहद ईमानदारी से काम किया, लेकिन विशेष रूप से बॉक्सर के रूप में पुलकित ने जिस अनुशासन और भावनात्मक परिपक्वता के साथ काम किया, उससे उनका यह परफॉर्मेंस, उनके करियर का सबसे दमदार किरदार बन गया।

अरिहंत परमात्मा का जीवन हमें राग और द्वेष से मुक्त होने की प्रेरणा देता है : आचार्यश्री पार्श्वचंद्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। 'अरिहंत अर्थात आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाला। नवकार मंत्र का प्रथम पद है अरिहंतों को नमस्कार। इसमें किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है अपितु गुणों की पूजा है। हम जिन गुणों के प्रति अपने अंतर्मन में अहो भाव रखेंगे, प्रमोद भाव रखेंगे वैसे ही गुण हमारे में प्रकट होंगे।' यह विचार मंगलवार को गणेशबाग में 15 दिवसीय आत्म आराधना उपधान प्रथम सोपान में आचार्य पार्श्वचंद्रजी ने आराधकों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संसार में 84 लाख जीव योनियों में जन्म मरण के परिभ्रमण से मुक्ति चाहिए तो आत्मा से द्वेष भाव को दूर करने के साथ ही राग भावों को भी दूर करना पड़ेगा। सांसारिक पदार्थों एवं प्रवृत्तियों में राग अर्थात आसक्ति जीव का संसार में परिभ्रमण को बढ़ाने वाली है।

संतश्री पदमचंद्रमुनिजी ने जीवन में व्रत आराधना का महत्व बताते हुए कहा कि जब तक हम व्रत धारण करके पाप कार्यों का त्याग करने का संकल्प नहीं लेते हैं तब तक दुनिया भर के पाप हमारे लिए

खुले रहते हैं और उसके कारण हमारी आत्मा के साथ निरंतर कर्मबंधन चालू रहते हैं। व्रत धारण करने से जिन पाप कार्यों को हम नहीं कर रहे हैं उनके त्याग का संकल्प हो जाता है और उन पाप कर्मों के बंधन से हम बच जाते हैं। उन्होंने कहा, जीवन में कई बार राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपराधी को दंड आवश्यक हो जाता है, लेकिन कभी भी निरपराध की हिंसा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा भी विवेक रखें तो अनावश्यक हिंसा से बच सकते हैं। उन्होंने दूसरे अणुव्रत सत्य का विवेचन करते हुए कहा कि जीवन में कन्या संबंधी, गौ आदि पशु संबंधी, भूमि संबंधी, किसी द्वारा रखी गई अमानत संबंधी बात में एवं किसी भी प्रकार की साक्षी में असत्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरलता का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि आत्मा की उन्नति चाहते हैं तो कपट को त्यागना होगा। कपट से आत्मा की अवनति प्रारंभ हो जाती है। जयधुरंदरमुनिजी ने 12 भावनाओं की अनुप्रेक्षा के क्रम में अशरण भावना का वर्णन किया। जयपुरंदरमुनिजी ने भी प्रेरक जीवन के सूत्र बताए। प्रातः काल में समणी निर्देशिका डॉ. सुयशनिधिजी ने आराधकों को अणुप्पेहा ध्यान साधना का प्रशिक्षण दिया। आयोजन के संयोजक राजेंद्रकुमार नाहर ने बताया कि आराधकों ने अनेक धार्मिक क्रियाएं संपन्न की। सहसंयोजक कोमलचंद धोका ने बताया कि इस अवसर पर चेन्नई से आई विशेष अतिथि खम्माबाई ज्ञानचंद मुणोत, जयमल जैन श्रावक संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाशचंद्र बोहरा, बेंगलूरु शाखा के अध्यक्ष मीठालाल लोढ़ा, गणेशबाग शिवाजीनगर के मंत्री संपतराज मांडोत, जयमल संघ के पूर्व अध्यक्ष मीठालाल मकाणा एवं पूर्व मंत्री कनकराज चोरड़िया आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन मनोहरलाल डूंगरवाल ने किया।

ताऊ, चाचा, बुआ, मामा और मासी के रिश्ते कहीं केवल 'अंकल-आंटी' में न सिमट जाएं : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बल्लारी। शहर के फोर्ट क्षेत्र में आयोजित कृतज्ञता महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को नवग्रह शांति अनुष्ठान के दौरान जैनाचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था और एक समान रक्त संबंधों के आधार पर विभिन्न समाजों की निर्मिति हुई थी।हजारों वर्षों से यही सामाजिक परिपाटी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है।अंतरजातीय विवाह की मान्यता इन प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने जैसा है। इस प्रकार करने से एक समय ऐसा आएगा कि लोगों को अपनी सामाजिक परंपरा और रक्त के संबंधों का कुछ भी पता नहीं चलेगा, पश्चिम में यही हुआ है। अंग्रेजों के शासनकाल से यह भ्रष्टता भारत में पनप रही है। डेढ़ सौ वर्षों की उनकी गुलामी ने हमारी हजारों-हजारों वर्षों की सांस्कृतिक परंपरा को नष्ट करने का प्रयास किया है। उनके कानूनों ने अंतरजातीय विवाह को संवैधानिक बना दिया है। यह भारत की संस्कृति के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। प्राचीन भारत देश की सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी रही हैं कि यहां अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे। हर समाज अपने दायरे में ही विवाह और आवश्यक व्यवहार करता था। छठी शताब्दी में भारत की यात्रा पर आये बौद्ध चीनी यात्री हुएन सांग ने भी अपनी डायरी में इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि भारत में अंतरजातीय विवाह नहीं होते। प्राचीन काल में दादा, दादी, नाना और नानी का गौत्र छोड़कर विवाह के संबंध स्थापित करने की परंपरा थी। यह व्यवस्थाएं रक्त की शुद्धता, गुणवत्ता तथा जातक के स्वास्थ्य एवं पराक्रम को दृष्टिकोण में रखते हुए स्थापित की गईं थी। करीब करीब हर भारतीय समाज इसका समुचित परिपालन करता था।

आचार्य विमलसागरसूरीश्वर ने कहा कि अंतरजातीय विवाह की परंपरा के बाद समाज और उसकी व्यवस्थाएं ही समाप्त हो जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि भाई-बहन जानकारीपूर्वक या अनजाने में शादियां कर लेंगे। सामाजिक व्यवस्थाएं ही भ्रष्टाचार को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। समाज के नष्ट होते ही अनेक सामाजिक रिश्ते भी नष्ट हो जाएंगे। पश्चिम में ताऊ, चाचा, बुआ, मामा और मासी के संबंधों का लगभग कुछ पता नहीं होता। एक दिन अपने देश भारत में भी सभी रिश्ते अंकल और आंटी के दायरे में सिमट कर रह जाएंगे। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और घातक होगा।

गणि पद्मविमलसागरजी ने बताया कि मंगलवार को मातृ-पितृ वंदना के साथ हुआ नवग्रह शांति अनुष्ठान व कृतज्ञता महोत्सव में मातृ-पितृ वंदना के साथ नवग्रह शांति अनुष्ठान और वस्तु देवताओं का पूजन विधान हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में देश के विभिन्न शहरों से श्रद्धालु शामिल हुए। बेंगलूरु के प्रसिद्ध संगीतकार विपिन पोरवाल ने अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां देकर उत्सव को भव्यता प्रदान की।

गौहत्या के विरोध में हमें एकजुट व संगठित होना अति आवश्यक : राष्ट्रसंत कमलमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के महावीर जैन हॉस्पिटल में विराजित राष्ट्रसंतश्री कमलमुनिजी कमलेश ने उपस्थितजन को संबोधित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बकरी ईद पर गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, इस आदेश को केंद्र और राज्य सरकार से कठोरता से पालन करवा करके संविधान की रक्षा के लिए आगे आएं। संतश्री ने कहा कि बकरीद पर मुस्लिम समाज के सबसे बड़े संगठन दारूल उलूम ने भी जन भावना का सम्मान करते हुए ईद पर गौ हत्या नहीं करने का आदेश जारी किया है और कहा है कि हिंदुओं की भावना का सम्मान करें। संतश्री ने बताया कि गोहत्या रोकने के लिए देशभर में गोभक्तों प्रयासरत है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की नई सरकार से आगामी बकरीद पर गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने के लिए गौभक्तों से देशव्यापी जनजागरण अभियान तेज करने की बात कही। उन्होंने देशभर के गोभक्तों, धर्मप्रेमियों एवं गौसेवकों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री एवं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का आह्वान किया। जैन संत ने कहा कि 26 मई को आने वाली बकरीद पर प्रदेश में गोहत्या पूर्णतः प्रतिबंधित की जाए तथा हाईकोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाए।ङ्गउन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक भावना का विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा से जुड़ा राष्ट्रीय विषय है। गौ समर्थकों ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र एवं राज्य सरकार न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए गोसंरक्षण की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगी।

तेयुप विजयनगर ने ओपीजी एक्स-रे मशीन का किया उद्घाटन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय तेरापंथ युवक परिषद विजयनगर द्वारा हम्पी नगर स्थित आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर में ओपीजी एक्स-रे मशीन का विधिवत लोकार्पण किया गया। अभातेयुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन मांडोत ने एक्स-रे मशीन पर स्वास्तिक अंकन कर शुभारंभ किया। तेयुप विजयनगर के अध्यक्ष विकास बांठिया ने उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए ओपीजी एक्स-रे मशीन के उद्घाटनकर्ता मार्गदर्शन फाउंडेशन के कमलेश-भरत डूंगरवाल के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही प्रायोजक के रूप में हनुमानमल, संजय, मनोज बैद परिवार तथा सहप्रायोजक सुरेश, करण, निखिल मांडोत परिवार व सुशीलादेवी, अरविंद, हिम्मत, पवन मांडोत परिवार के सहयोग हेतु धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सेन्टर के डॉक्टर्स की टीम के साथ अभातेयुप, तेयुप व अन्य संबंधित संस्थाओं के सदस्य उपस्थित थे।

देवी उत्सव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

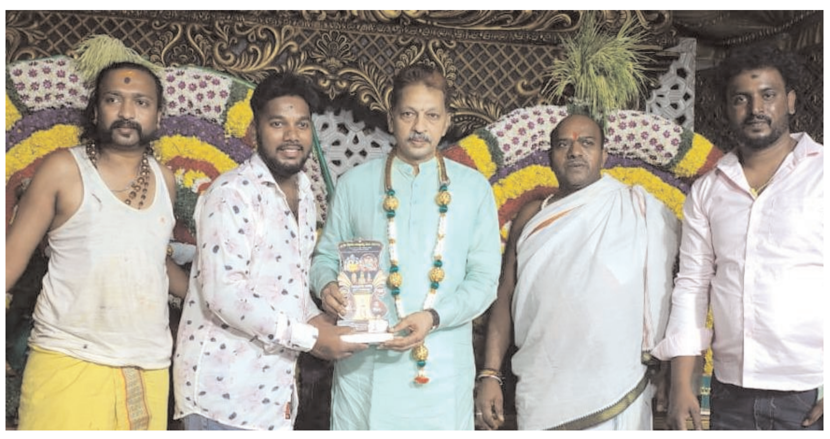

बेंगलूरु के शक्ति देवी मधुरामा सेवा समिति सुब्रह्मण्यनगर द्वारा आयोजित 'उर हब्बा करगा महोत्सव' कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित महेंद्र मुणोत ने देवी मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मुणोत ने कार्यक्रम में अन्नदान कार्यक्रम में सेवा प्रदान की।आयोजकों ने मुणोत को सम्मानित किया।

शीर्ष अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ टीवीके विधायक की याचिका पर सुनवाई करेगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/चेन्नई। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत के दौरान मतदान में हिस्सा लेने से रोकने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले टीवीके के एक विधायक की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के नेता सी जोसेफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। टीवीके विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा प्रस्तुत किया गया। पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने पर सहमति जताई।

सेतुपति ने शिवगंगई जिले के नंबर 185 तिरुपत्तुर विधानसभा क्षेत्र में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता एवं पूर्व मंत्री के. आर. पेरियाकरुप्पन के खिलाफ एक मत के अंतर से जीत हासिल की थी। इसके बाद पेरियाकरुप्पन ने मतगणना प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में सेतुपति के, तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत समेत किसी भी मतदान में हिस्सा लेने पर अंतरिम रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि श्रीनिवास सेतुपति किसी अविश्वास प्रस्ताव पर भी मतदान नहीं कर सकेंगे। इस आदेश का तमिलनाडु विधानसभा की 234 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में इस गठबंधन को 120 विधायकों का समर्थन प्राप्त है।

सेतुपति को मतदान की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिए जाने के कारण, सदन में उसकी प्रभावी संख्या घटकर 119 हो जाएगी। उच्च न्यायालय के समक्ष, पेरियाकरुप्पन ने आरोप लगाया कि तिरुपत्तुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 185 के लिए भेजा जाने वाला एक डाक मतपत्र गलती से तिरुपत्तुर जिले के तिरुपत्तुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 50 में भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि मतपत्र को विचार के लिए सही निर्वाचन अधिकारी के पास भेजने के बजाय वहीं खारिज कर दिया गया था।

उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की गिनती में कथित विसंगतियों की ओर भी इशारा किया और दावा किया कि मतगणना रिकॉर्ड और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़ों के बीच 18 मतों का अंतर था। अंतरिम आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने पाया कि सीमित निर्देश के लिए प्रथमदृष्टया मजबूत मामला बनता है। हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि यह आदेश सेतुपति के निर्वाचन को रद्द नहीं करता और न ही पेरियाकरुप्पन को निर्वाचित घोषित किये जाने का कोई अधिकार प्रदान करता है।

भाजपा ने सनातन विरोधी टिप्पणी को लेकर उदयनिधि स्टालिन की आलोचना की

नई दिल्ली/चेन्नई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर किए गए नए हमलों की कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही पार्टी ने उन पर तथा अन्य विपक्षी दलों पर वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन के खिलाफ नफरत फैलाने में लिप्त होने का आरोप लगाया। भाजपा की प्रतिक्रिया उदयनिधि स्टालिन द्वारा मंगलवार को सनातन धर्म को समाप्त करने का आह्वान करने के बाद आयी है। स्टालिन ने दावा किया कि सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है। उन्होंने सितंबर 2023 में भी इस तरह की विवादास्पद टिप्पणी की थी।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि ''तमिलनाडु में द्रमुक की चुनावी हार के बावजूद, उदयनिधि स्टालिन फिर वही करने लगे हैं जो वे सबसे अच्छा करते हैं – सनातन धर्म का अपमान और उसके खिलाफ नफरत फैलाना।''

पूनावाला ने कहा, ''उन्होंने अब विधानसभा में कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। पिछली बार जब उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की थी, तब उच्चतम न्यायालय ने भी उसे नफरती भाषण करार दिया था।'' उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम .के. स्टालिन ने उस समय हुए विवाद को लेकर अपने बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्हें उपमुख्यमंत्री बना दिया, जबकि कांग्रेस ने भी उन टिप्पणियों की निंदा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता पूनावाला ने कहा, चुनावी हार और लोगों द्वारा उनके हिंदू-विरोधी और सनातन-विरोधी दृष्टिकोण को खारिज किए जाने के बावजूद, उन्होंने कोई सबक नहीं लिया है।

'नेक्स्टजेन टॉक्स, मास्टर दि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग' कार्यशाला का हुआ आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जीतो) साउथ लेडीज़ विंग ने सक्षम पहल के अंतर्गत किशोरों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला 'नेक्स्टजेन टॉक्स, मास्टर दि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग' का शुभारंभ मंगलवार को जीतो कार्यालय चामराजपेट में हुआ। इस कार्यशाला में 35 किशोर शामिल हुए। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, प्रभावी संवाद कौशल एवं समाज सेवा की भावना विकसित करना है, ताकि वे भविष्य में सशक्त और प्रेरणादायी नेतृत्वकर्ता बन सकें। लेडीज विंग, साउथ की चेयरपर्सन बबिता रायसोनी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि नेक्स्टजेन टॉक्स केवल पब्लिक स्पीकिंग सिखाने का मंच नहीं है, बल्कि यह बच्चों को अपनी आंतरिक आवाज़ पहचानने, आत्मविश्वास विकसित करने और अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। ङ्गङ्गसंयोजिका निशा कोठारी ने पायलट फैकल्टी अमित सिंघवी का परिचय कराया, वहीं सह संयोजिका निशा तुकलिया ने को-पायलट फैकल्टी कृषा शाह का परिचय दिया। प्रशिक्षकों ने बताया कि यह कार्यशाला केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें अनेक व्यवहारिक गतिविधियां, खेल, रोल प्ले, टीम गतिविधियां एवं स्टेज एक्सरसाइज के माध्यम से बच्चों को सीखने का अवसर मिलेगा। कार्यशाला के प्रथम दिन आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़, टीम फॉर्मेशन एवं प्रतिभागियों के परिचय के साथ शुरुआत हुई। प्रतिभागियों को बताया गया कि नियमित अभ्यास, सही मार्गदर्शन एवं आत्मविश्वास से पब्लिक स्पीकिंग के डर को कैसे दूर किया जा सकता है ।प्रशिक्षकों ने यह भी समझाया कि प्रभावी संवाद कौशल केवल मंच तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह नेटवर्किंग, मित्रता, करियर विकास, नेतृत्व और जीवन में सफलता प्राप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सत्र में बच्चों को औपचारिक एवं अनौपचारिक अवसरों के अनुसार ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज, पोस्टर, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन, उच्चारण, मुस्कान के महत्व तथा मंच पर आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत होने की बारीकियाँ विस्तार से सिखाई गईं। ङ्गङ्गकार्यशाला में पिक एंड स्पीक, करंट टॉपिक्स पर डिबेट, स्टेज प्रोटोकॉल स्पीच, अतिथि परिचय भाषण, धन्यवाद ज्ञापन, पर्सुएसिव स्पीच जैसे अनेक रोचक सत्र हुए। प्रतिभागियों ने भी अत्यंत उत्साह के साथ अपने विचार, सपने और सीखने की इच्छाएँ साझा कीं।

कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चयन में गठबंधन की कोई भूमिका नहीं : हासन

तिरुवनंतपुरम/दिल्ली। केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की चुनावी जीत के बाद मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम एम हासन ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन में गठबंधन की कोई भूमिका नहीं है। सहयोगी दलों के रुख से निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंकाओं को खारिज करते हुए हासन ने कहा कि विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री का चयन कांग्रेस स्वयं करेगी।

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी आलाकमान द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लेने से पहले नयी दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस स्वयं अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेगी। गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं करते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के प्रमुख घटक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन को दिए गए समर्थन से संबंधित सवालों के जवाब में उन्होंने ये टिप्पणी की।

केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा के लिए दिल्ली आमंत्रित वरिष्ठ नेताओं में से एक हासन ने मुख्यमंत्री की घोषणा में देरी को लेकर हो रही आलोचना को भी कम करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आमतौर पर चुनाव के बाद विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री का फैसला करने में लगभग एक सप्ताह का समय लेती है और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की असामान्य देरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा, यूडीएफ सत्ता में इसलिए आया क्योंकि जनता की राय उसके पक्ष में थी। आलाकमान ने निर्वाचित विधायकों से राय ली है और अब हमसे भी परामर्श कर रहा है।

तीन चोरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य के आभूषण बरामद किए

बेंगलूरु। यहां केआर पुरम पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों रुपए चोरी के माल को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने राजस्थान से गोपाल (29), कैलाश (30) और उत्तरप्रदेश से नागेन्द्र साहनी (30) को गिरफ्तार किया है। केआरपुरम में रहने वाले छल्लाराम चौधरी ने अपनी एक शिकायत में बताया कि गत 18 फरवरी को उसके घर से चोरी हो गई थी। चौधरी अपने परिवार के सुबह एक कार्यक्रम के लिए टीसी पाल्या गए हुए थे, घर में ताला लगा देखकर चोरों ने घर से साढे चार लाख रुपए नकद और 50 लाख रुपए मूल्य के सोना चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए राजस्थान के जालोर क्षेत्र से गोपाल और कैलाश को गिरफ्तार किया वहीं उत्तरप्रदेश से नागेन्द्र साहनी को गिरफ्तार कर सोमवार को बेंगलूरु लाई।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**